Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 64
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
गुरूवार, 12 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

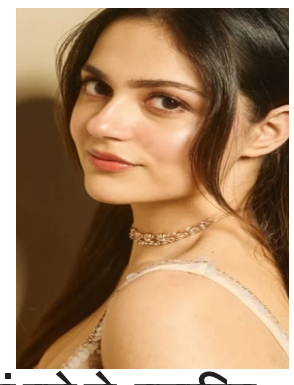

3 देश का पहला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था...

4 वैश्विक राजनीति के कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र ...

7 पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश : पहले वनडे में ...

संक्षिप्त न्यूज

हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए धामी सरकार का मेगा प्लान, 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 1000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना तथा उत्तराखंड को एक प्रमुख तीर्थ और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार गंगा, यमुना, चार धाम, आदि कैलाश और कई शक्तिपीठों की पवित्र भूमि उत्तराखंड लंबे समय से दुनिया भर के सनातन अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में हरिद्वार कुंभ मेला, हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, नंदा देवी राज जाट यात्रा और सरयू नदी तट विकास जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ-केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना पर भी कार्य जारी है।

राज्य सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत 48 मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास का काम भी शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य मंदिरों तक पहुंच को बेहतर बनाना और तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा आगामी नंदा देवी राज जाट यात्रा के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शीतकालीन चार धाम यात्रा भी शुरू की है। बजट में सरयू नदी तथा अन्य नदी तट विकास परियोजनाओं, हरिपुर-कालसी स्थित यमुना घाट के विकास और आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र के विकास के लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है।

तिरुचिरापल्ली से पीएम मोदी का डीएमके पर बड़ा हमला

कहा- जनता ने बदलाव का मन बना लिया है

तिरुचिरापल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र के लिए एक विकसित तमिलनाडु का निर्माण करना है। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से ऊर्जा की उपलब्धता और कनेक्टिविटी में सुधार होगा और तमिलनाडु के युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि आज हम 370 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है। इनमें से प्रत्येक सड़क केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, छात्र आराम से स्कूल और कॉलेज जा सकेंगे और किसान अपनी उपज बेचने या अन्य सामान खरीदने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा सकेंगे। कुल मिलाकर, प्रत्येक सड़क ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और

जीवन स्तर को सुगम बनाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सप्ताह ही हमने मदुरै से अमृत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 8 आधुनिक और पुनर्निर्मित स्टेशनों का उद्घाटन किया। आज कई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। ये सेवाएं नागरकोइल, रामेश्वरम आदि को अन्य क्षेत्रों से जोड़ती हैं। इन नई रेल सेवाओं से पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे। हमारा लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र के लिए एक विकसित तमिलनाडु का निर्माण करना है।

तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिची साहस और आस्था की भूमि है। इसने मरुधु बंधुओं की वीरता देखी है। मुझे मेजर एम. सरवनन भी याद हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया। तमिलनाडु और उसकी संस्कृति का सम्मान करने में हमारी सरकार हमेशा अग्रणी रही है। यह गर्व की बात है कि तमिलनाडु के सपूत सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने सम्राट पेरुम्बिडुगु मथारैयार के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। यह तमिलनाडु के लिए गौरव का क्षण था।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं राज्य की नब्ज़ को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। आदि मास में कावेरी नदी अदम्य शक्ति से बहती है। ठीक उसी तरह, तमिलनाडु में इस चुनावी मौसम में बदलाव की चाहत ज़ोरों से बढ़ रही है। पूरे राज्य ने डीएमके को सरकार से बाहर करने का मन बना लिया है। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो हर परिवार के लिए काम करे, और वे जानते हैं कि केवल एनडीए ही तमिलनाडु में यह बदलाव ला सकता है।

कांग्रेस ने सरकार से पूछे तीखे सवाल

'रूस से तेल खरीदने की अनुमति वाला अमेरिकी बयान भारत का अपमान'

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट के इस बयान के बाद उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया कि अमेरिका ने भारत को अस्थायी रूप से रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी थी। लीविट ने यह भी कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत एक अच्छा पक्षधर रहा है। उसने पहले प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था। कांग्रेस ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए अनुमति प्राप्त और अच्छा अभिनेता शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही केंद्र को इस बात पर घेर लिया कि यह हमारी संप्रभुता और गरिमा का घोर अपमान है।

सरकार अपमान पर आपत्ति क्यों नहीं जता रही

कांग्रेस ने एक पोस्ट में कहा 'व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। भारतीयों को अच्छे अभिनेता बताया है। इसे फिर से पढ़ें, अनुमति दी, अच्छे अभिनेता। पार्टी ने आगे कहा, 'भारत सरकार हमारी संप्रभुता और गरिमा के इस घोर अपमान पर आपत्ति क्यों नहीं जता रही है? भारत के सम्मान की रक्षा करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर चुप रहना पसंद कर रहे हैं।' कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की चुप्पी का आरोप लगाते हुए उससे जवाब मांगा। उन्होंने कहा, 'इसलिए देश को यह पूछना चाहिएः वह किस बात से डर रहे हैं? भारत के फैसले बाहर से क्यों निर्देशित किए जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी को अमेरिका ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? भारत की जनता जवाब पाने की हकदार है। क्योंकि भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।'

वेस्ट गारो हिल्स में 13 मार्च तक के लिए बढ़ा कर्फ्यू, जिले में स्थानीय परिषद के चुनाव टले

शिलांग। मेघालय में पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कर्फ्यू दो दिन के लिए बढ़ा दिया। मंगलवार को मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स ज़िले में दो ग्रुप्स के बीच झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारी ने बताया जिले में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर रोक जारी रहेगी। कर्फ्यू 13 मार्च को सुबह 12 बजे तक रहेगा। राज्य में आर्मी समेत और सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई हैं।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हिंसा को देखते हुए गारो हिल्स के स्थानीय परिषद के चुनावों को टालने का एलान किया है। पहले यह चुनाव 10 अप्रैल को होने वाले थे। मंगलवार को गारो हिल्स में स्थानीय परिषद चुनावों चुनाव के नामांकन हो रहा था। प्रक्रिया के दौरान ट्राइबल और नॉन-ट्राइबल ग्रुप्स के बीच झड़प के दौरान पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई थी

उपायुक्त वी अग्रवाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू 13 मार्च को सुबह 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। एक और अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन का मदद के लिए सेना की पांच टुकड़ियां तैनात की गई हैं। तीन टुकड़ियां मंडल मुख्यालय, तुरा शहर में तैनात की गई हैं, जबकि दो टुकड़ियां चिबिनंग में तैनात की गई हैं।

लोकसभा में गिरा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया जोरदार पलटवार

नई दिल्ली। सदन में तीखी बहस के बाद लोकसभा ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ध्वनिमत से मतदान के बाद प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने प्रस्ताव का विरोध किया था। बहस के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर का जोरदार बचाव किया और विपक्ष पर संसदीय परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी लगातार विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया और उन पर संसद में बोलने की अनुमति न मिलने की गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। गांधी की विदेश यात्राओं का विशेष रूप से जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि जब सदन में बोलने का मौका होता है, तो कांग्रेस नेता बहसों में भाग लेने के बजाय जर्मनी या इंग्लैंड में नजर

आते हैं।

शाह की ये टिप्पणियां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर गरमागरम बहस के दौरान आईं। गृह मंत्री ने विपक्ष के नेता की आवाज दबाए जाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि बहसों के दौरान कब बोलना है, यह तय करना सदस्यों का अपना अधिकार है। शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता को शिकायत है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनकी आवाज दबाई जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन तय करेगा कि किसे बोलना है? अध्यक्ष? नहीं, यह आपको तय करना है।

उन्होंने आगे कहा कि 18वीं लोकसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस सांसदों ने सामूहिक रूप से 157 घंटे और 55 मिनट तक भाषण दिया, और सवाल उठाया कि गांधी जी ने स्वयं इन अवसरों का लाभ क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि लेकिन जब बोलने का मौका मिलता है, तो आप जर्मनी या इंग्लैंड में नजर आते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं... कांग्रेस सांसदों ने 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट तक भाषण दिया। विपक्ष के विपक्ष ने कितना भाषण दिया? आप क्यों नहीं बोले? किस स्पीकर ने आपको रोका? कोई नहीं रोक सकता। लोकसभा को बदनाम करने के लिए गलत सूचना फैलाई जा रही है। इससे पहले, स्पीकर के पद का बचाव करते हुए, शाह ने बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की। गृह मंत्री के अनुसार, ऐसा कदम संसदीय संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। पिछली संसदीय परंपराओं को याद करते हुए, शाह ने कहा कि जब भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन विपक्ष में था, तब उसने कभी भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास नहीं किया।

पश्चिम एशिया संकट का असर! एलपीजी आपूर्ति पर सरकार का आश्वासन, जमाखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि देश में एलपीजी की 100 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और सामान्य रूप से ढाई दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी जारी रहेगी।

सरकार के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंका के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र ने प्राकृतिक गैस और खाना पकाने वाली गैस पर नियंत्रण संबंधी कदम उठाए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह सचिव ने एलपीजी की स्थिति पर सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। राज्यों से कहा गया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए तथा देशभर में एलपीजी का सुचारू और निष्पक्ष वितरण

सुनिश्चित किया जाए।

सरकार की ओर से आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठक में बताया गया कि अफवाहों के कारण लोग जल्दबाजी में सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर वितरण को नियंत्रित किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि देश में एलपीजी का लगभग 60 प्रतिशत आयात होता है, जिसमें से करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आती है। स्थिति को देखते हुए घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को गैर-घरेलू श्रेणी में रखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। भारत की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है और विविध स्रोतों से खरीद के कारण आवश्यक मात्रा सुरक्षित कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि भारत लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है और गैस कंपनियों ने नए स्रोतों से एलएनजी के कार्गो भी खरीदे हैं। दो एलएनजी कार्गो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं।

सरकार ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि घबराकर अतिरिक्त बुकिंग न करें, क्योंकि घरेलू एलपीजी की सामान्य आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है।

बीआरएस का राहुल गांधी पर तीखा हमला, केटीआर ने बताया 'संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन'

हैदराबाद। तेलंगाना में दलबदल के मुद्दे को लेकर बीआरएस और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें 'संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन' बताया।

केटीआर ने आरोप लगाया कि तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने कथित रूप से भारी दबाव में आकर दलबदल करने वाले विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ओर खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, जबकि दूसरी ओर दलबदल की राजनीति को बढ़ावा देते हैं।

मीडिया से बातचीत में केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 'आया राम गया राम' की राजनीति को बढ़ावा दे रही

है और संविधान पर हमला कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य जिम्मेदार हैं और तेलंगाना की जनता को इसका जवाब देना चाहिए।

यह विवाद तब बढ़ा जब तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष ने कथित तौर पर दलबदल करने वाले दो विधायकों – कडियाम श्रीहरि और दानम नागेंद्र – के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया।

दानम नागेंद्र ने खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र से बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन बाद में सिकंदराबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा।

इसके अलावा केटी रामाराव ने यह भी घोषणा की कि बीआरएस तेलंगाना विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान एक निजी सदस्य विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर जनता से किए गए वादों से विश्वासघात का आरोप लगाया जाएगा और चुनाव के समय किए गए छह प्रमुख वादों को कानूनी मान्यता देने की मांग की जाएगी।

स्पीकर ने दो विधायकों की अयोग्यता याचिकाएं खारिज कीं, कादियम श्रीहरी और दानम नागेंद्र को मिली राहत

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद राव ने बुधवार को बीआरएस के विधायक दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि दोनों विधायकों ने दल-बदल विरोधी नियमों का उल्लंघन किया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि दोनों विधायकों ने आधिकारिक रूप से पार्टी बदली है। उपलब्ध सामग्री और सुनवाई के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आया। इससे पहले अध्यक्ष ने इसी तरह के मामलों में आठ अन्य विधायकों को भी क्लीन चिट दी थी।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दानम नागेंद्र और कादियम श्रीहरि को क्लीन चिट देना लोकतंत्र पर हमला है। केटीआर ने इसे लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन बताते हुए कहा कि ऐसे फैसले राजनीतिक दलबदल को बढ़ावा देते हैं और लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए संवैधानिक सिस्टम का गलत इस्तेमाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता इस पर सही समय पर जवाब देगी।

दानम नागेंद्र ने किया पलटवार

दानम नागेंद्र ने केटीआर और भाजपा नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि बीआरएस विधायक दल की हाल की बैठक में उन्हें क्यों शामिल नहीं किया गया।

आबकारी नीति घोटाले में नया मोड़, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर उठाए सवाल, केस ट्रांसफर की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए केस को किसी अन्य पीठ में स्थानांतरित करने की मांग की है।

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए मामले को किसी अन्य उपयुक्त पीठ को सौंपा जाना चाहिए। इस मामले में केजरीवाल को प्रतिवादी संख्या 18 के रूप में नामित किया गया है।

अभ्यावेदन में कहा गया है कि 9 मार्च को हुई पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने नोटिस जारी करते हुए प्रारंभिक टिप्पणी की कि निचली अदालत का बरी करने का आदेश 'त्रुटिपूर्ण' था, जबकि अभी तक बरी किए गए आरोपियों की दलीलें सुनी ही नहीं गई थीं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि इस प्रकार की टिप्पणी से पूर्वाग्रह की आशंका उत्पन्न होती है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित कार्यवाही को प्रभावित करने वाले अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जबकि यह एजेंसी पुनरीक्षण याचिका में पक्षकार नहीं थी। सीबीआई द्वारा दायर याचिका में भी ईडी की कार्यवाही से संबंधित कोई राहत नहीं मांगी गई थी।

अभ्यावेदन में यह तर्क दिया गया कि यदि पुनरीक्षण याचिका के परिणाम को ईडी की कार्यवाही से जोड़ा जाता है, तो इसके व्यापक परिणाम हो सकते हैं क्योंकि ईडी का मामला उसी मूल अपराध पर आधारित है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

इसके अलावा जवाब दाखिल करने के लिए अदालत द्वारा दिए गए समय पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया कि मामले में बड़ी संख्या में दस्तावेज और कई आरोपपत्र शामिल हैं, इसके बावजूद जवाब दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया गया, जो सामान्यतः ऐसे मामलों में दिए जाने वाले समय से काफी कम है।

अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आबकारी नीति से जुड़े अन्य मामलों में भी इसी पीठ द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों में कुछ मुद्दों पर विस्तृत प्रारंभिक टिप्पणियां की गई थीं, जो वर्तमान पुनरीक्षण याचिका से संबंधित हैं।

विधानसभा में एमआईडीसी जमीन आवंटन पर हंगामा, सरकार ने एसआईटी जांच का दिया भरोसा

दिव्यांश

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा में एमआईडीसी जमीन आवंटन को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने अहिल्यानगर में लगभग 4,000 एकड़ जमीन के आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यह कीमती जमीन निजी और कॉर्पोरेट कंपनियों को बहुत कम कीमत पर दी जा रही है और इस प्रक्रिया में कई सरकारी नियमों की अनदेखी की गई है।

वडेट्टीवार ने कहा कि जमीन के इस ट्रांसफर से स्थानीय किसानों में भारी चिंता और नाराजगी है। उनका आरोप है कि औद्योगिक परियोजनाओं के नाम पर किसानों की खेती की जमीन कंपनियों को सौंप दी जा रही है।

इन आरोपों पर जवाब देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार इस मामले से अवगत है और

जमीन के म्यूटेशन तथा ट्रांसफर की प्रक्रिया में कुछ खामियां सामने आई हैं। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गहन जांच कराई जाएगी।

मंत्री ने घोषणा की कि इस पूरे लेनदेन की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाएगा। यह टीम तलाठी से लेकर वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों तक सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय करेगी।

बावनकुले ने स्पष्ट किया कि सरकार एमआईडीसी की जमीन का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग सहन नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है और यदि किसी पुराने आदेश से इन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सरकार कानूनी विशेषज्ञों की मदद भी लेगी।

सदन में चर्चा के दौरान कई विधायकों ने बड़े पैमाने पर जमीन हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ किसानों के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है और एमआईडीसी की जमीन का लाभ राज्य और किसानों दोनों को मिलना चाहिए, केवल निजी कंपनियों को नहीं।

सरकार ने बताया कि इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कैबिनेट की उपसमिति के पास भी भेजा जाएगा।

ऑपरेशन 'अमानत' के तहत यात्री का यात्रा में छूटा आई-फोन सुरक्षित लौटाया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा एवं उनकी खोई हुई वस्तुओं को वापस दिलाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में एक बार फिर तत्परता और संवेदनशीलता का उदाहरण देखने को मिला, जब यात्रा के दौरान सीट पर छूट गया एक यात्री का महंगा आई-फोन आरपीएफ द्वारा खोजकर सुरक्षित रूप से यात्री को लौटा दिया गया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 10 मार्च 2026 को यात्री श्री धवल ट्रेन संख्या 12927 एकतानगर-दादर एक्सप्रेस के कोच संख्यां-2 में दादर से वडोदरा की यात्रा कर रहे थे। वडोदरा स्टेशन पर उतरने के बाद जब वे स्टेशन से बाहर चले गए, तब उन्हें पता चला कि उनका आई-फोन ट्रेन की सीट पर ही छूट गया है।

यात्री द्वारा तत्काल रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर इसकी सूचना दी गई। सूचना प्राप्त होते ही रेलवे सुरक्षा बल की एकतानगर पोस्ट पर कार्यरत कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार तथा कांस्टेबल महेश चंद शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एकतानगर

स्टेशन के प्लेटफॉर्म लाइन संख्या 05 पर खड़ी उक्त ट्रेन के कोच संख्यां-2 की जांच की। जांच के दौरान मोबाइल फोन सीट पर सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुआ।

यात्री द्वारा बताए गए विवरण से मोबाइल का मिलान करने तथा आवश्यक सत्यापन के उपरांत हेड कांस्टेबल सतेंद्र कुमार द्वारा उक्त आई-फोन संबंधित यात्री को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया। अपना मोबाइल सुरक्षित वापस मिलने पर यात्री श्री धवल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा संचालित रेल मदद 139 हेल्पलाइन की त्वरित एवं प्रभावी सेवा की सराहना की। साथ ही उन्होंने आरपीएफ एकतानगर पोस्ट की तत्परता तथा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमानत' के सराहनीय कार्यों की भी प्रशंसा की।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी वस्तु के छूट जाने या आपात स्थिति में तुरंत रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा 'ऑपरेशन अमानत' यात्रियों की खोई हुई वस्तुओं को खोजकर उन्हें सुरक्षित लौटाने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य कर रहा है, जिससे यात्रियों में रेलवे के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ हो रही है।

भूमि अभिलेख विभाग की 2003 से लंबित योजना को मिली मंजूरी– राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य के भूमि अभिलेख विभाग की 2003 से लंबित संरचना को मंजूरी दे दी गई है और इस विभाग में 10,683 पदों की संरचना तय की गई है। इसके साथ ही राज्य में आधुनिक तकनीक की मदद से भूमि अभिलेख व्यवस्था को सुधारकर अधिक सक्षम और पारदर्शी प्रणाली बनाने का लक्ष्य है, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में बताया।

इस विषय पर सदस्य गोपीचंद पडळकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। इस चर्चा में सदस्य बाबनराव लोणीकर, राजेश पवार और अभिजीत पाटिल ने भी भाग लिया।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार के 100 और 150 दिनों के प्रशासनिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेख विभाग के लंबित मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षकों के पदोन्नति के लिए भी कदम उठाए हैं और निर्णय लिया गया है कि 40 प्रतिशत पद पदोन्नति से, 40 प्रतिशत आंतरिक परीक्षा के माध्यम से तथा 20 प्रतिशत पद सीधे भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे एस-6 श्रेणी के कर्मचारियों को एस-8 श्रेणी में पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले तीन वर्षों में एस-6 श्रेणी समाप्त कर दी जाएगी और सभी भूमि

सर्वेक्षक एस-8 श्रेणी में पदोन्नत होंगे।

भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग को 135 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से 1200 आधुनिक 'रोवर्स' उपकरण खरीदे जा रहे हैं। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 300 और रोवर्स उपलब्ध होने की संभावना है तथा अन्य निधियों से 500 से 600 रोवर्स और प्राप्त करने की योजना है। इस प्रकार राज्य में कुल लगभग 2500 रोवर्स उपलब्ध होंगे, जिससे लंबित सर्वेक्षण जल्द पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि सर्वेक्षण प्रक्रिया में देरी कम करने के लिए कानून में संशोधन किया गया है और जिला कलेक्टरों को सरकारी भूमि सर्वेक्षकों की सहायता के लिए लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षकों को प्रशिक्षण देकर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इससे सर्वेक्षण की गति चार गुना बढ़ गई है और 30 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए एक और राजस्व आयुक्तालय तथा उपनिदेशक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कार्यालय नांदेड़ या लातूर में स्थापित करने का निर्णय शीघ्र लिया जाएगा, ऐसी जानकारी भी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी।

मल्हारगढ़-मंदसौर रेल खंड का सीआरएस निरीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न

नीमच-रतलाम रेल खंड के दोहरीकरण का 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण

रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के अंतर्गत लगभग 133 किलोमीटर लंबे नीमच-रतलाम रेल खंड के दोहरीकरण का कार्य तेज गति से प्रगति पर है। इस परियोजना के तहत 10 एवं 11 मार्च 2026 को मल्हारगढ़-मंदसौर रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

पश्चिम परिमंडल के रेल संरक्षा आयुक्त श्री ई. श्रीनिवास ने 10 मार्च 2026 को मल्हारगढ़-मंदसौर रेल खंड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नवीन दोहरीकृत रेल लाइन के अंतर्गत निर्मित पुलों, ओवरहेड इक्विपमेंट (ओएचई), रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग व्यवस्था तथा अन्य सभी संरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण किया।

इसके पश्चात 11 मार्च 2026 को इस नवीन दोहरीकृत खंड पर निरीक्षण यान को 120 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक गति से चलाकर ट्रैक की गुणवत्ता और संरक्षा मानकों की जांच की गई।

निरीक्षण एवं गति परीक्षण संतोषजनक पाए जाने के उपरांत रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा मल्हारगढ़-मंदसौर रेल खंड पर यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी किया

गया।

मल्हारगढ़-मंदसौर खंड के लगभग 23.35 किलोमीटर लंबे दोहरीकृत ट्रैक को ट्रेन संचालन की अनुमति मिलने के साथ ही नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना का लगभग 85 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 133 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड में से अब तक लगभग 115 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण पूरा किया जा चुका है और हम नीमच-रतलाम दोहरीकरण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। इस परियोजना के शेष हिस्सों अर्थात मंदसौर-दलौदा रेल खंड तथा रतलाम-धौसवास रेल खंड पर कार्य तीव्र गति से जारी है। रेलवे प्रशासन द्वारा इन शेष खंडों के दोहरीकरण कार्य को भी शीघ्र पूर्ण कर ट्रेन संचालन के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

नीमच-रतलाम रेल खंड का दोहरीकरण पूर्ण होने के पश्चात रतलाम-चित्तौड़गढ़ रेल खंड पूर्णतः दोहरीकृत एवं विद्युतीकृत रेल मार्ग बन जाएगा। इससे इस सेक्शन की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दोहरीकरण से ट्रेनों के क्रॉसिंग एवं पासिंग में लगने वाले समय में कमी आएगी, जिससे यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा तथा यात्रियों को अपने गंतव्य स्टेशन तक शीघ्र पहुंचने में सुविधा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त रतलाम-चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित सीमेंट, जिंक तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए मालगाड़ियों की आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी। इससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को भी गति मिलने की संभावना है।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा इस महत्वपूर्ण दोहरीकरण परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों और उद्योगों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मनपा बजट स्थायी सीमित के हवाले कुल 1439 करोड का बजट पेश

16 मार्च को महासभा मे बजट अंतरिम रूप से पेश करने का अनुमान

मिरा-भाईंदर। मंत्र भारत

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका का वर्ष 2026-27 के लिए बजट मंगलवार को महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा ने स्थायी समिति के सभापति हसमुख गेहलोत के समक्ष पेश किया। शासन निधि को अलग रखते हुए 1,439 करोड़ रुपये का बजट 15 करोड़ 22 लाख 128 हजार रुपये की शिल्लक के साथ प्रस्तुत किया गया।

इस वर्ष शासन निधि 2,576 करोड़ रुपये, कर्ज 445 करोड़ 98 लाख रुपये तथा महानगरपालिका निधि को मिलाकर कुल 4,481 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। यह पिछले वर्ष के लगभग 2,694 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में करीब 1,787 करोड़ रुपये अधिक है।

गौरतलब है कि पिछले तीन वर्षों से महापालिका में प्रशासनिक राज होने के कारण बिना किसी चर्चा के प्रशासन द्वारा पेश किया गया बजट मंजूर हो जाता था। लेकिन दो महीने पहले हुए महापालिका चुनावों के बाद अब जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं। इसी कारण इस बार बजट को स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए रखा गया है। इस पर विस्तृत चर्चा के बाद

महत्वपूर्ण विभागों के लिए बजट प्रावधान

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा दैनिक सफाई और नाले सफाई के लिए - 214 करोड़ 29 लाख रुपये
घनकचरा प्रबंधन - 50 करोड़ 37 लाख रुपये
पानी आपूर्ति - 25 करोड़ 93 लाख रुपये
महिला एवं बाल कल्याण विभाग - 28 करोड़ 49 लाख रुपये
अंध व दिव्यांग कल्याण विभाग - 28 करोड़ 49 लाख रुपये
दुर्बल घटक योजना - 28 करोड़ 49 लाख रुपये
नगररचना विभाग - 42 करोड़ 45 लाख रुपये
शिक्षा विभाग - 35 करोड़ 28 लाख रुपये
वैद्यकीय स्वास्थ्य विभाग - 60 करोड़ 39 लाख रुपये
संगणक विभाग - 15 करोड़ 39 लाख रुपये
उद्यान विकास - 53 करोड़ 87 लाख रुपये
परिवहन सेवा - 35 करोड़ रुपये
विद्युत विभाग - 60 करोड़ 75 लाख रुपये
निर्माण विभाग - 243 करोड़ 37 लाख रुपये
कर्मचारी वेतन (आस्थापना विभाग) - 55 करोड़ 35 लाख रुपये
पानीपुरवठा विभाग - 259 करोड़ 31 लाख रुपये
पर्यावरण विभाग - 10 करोड़ 30 लाख रुपये

16 मार्च को होने वाली महासभा में अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

विशेषज्ञ क्या कहते है?

जानकारो का कहना है कि कर्ज और अनुदान की राशि पर निर्भर मिरा-भाईंदर का यह बजट कम होना ही दर्शाता है की मनपा को इस वर्ष अपने योजनाओ को कार्यशील रखने के लिए अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करनी होगी जो इस बजट के मुताबिक कडी चुनौती साबित होगा। कई जानकारो का मानना है कि यह बजट शहर के विकास के लिए कोई बडी परियोजना की ओर इशारा नही करया दिख रहा है।'

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मनपा द्वारा कार्यक्रम

मंत्र भारत। भाईदंर

8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने महिलाओं के लिए एक खास प्रोग्राम रखा। यह कार्यक्रम महापौर डिंपल मेहता की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर कमिश्नर राधाबिनोद ए. शर्मा और डिप्टी मेयर ध्रुवकिशोर पाटिल मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण से जुड़े अलग-अलग टॉपिक पर वार्ता की गई और समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मानित किया गया।

एडिशनल कमिश्नर डॉ. संभाजी पनपट्टे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हसमुख गहलोत, डिप्टी कमिश्नर कविता बोरकर, डिप्टी कमिश्नर प्रणाली घोंगे, महिला एवं बाल कल्याण कमेटी अनीता जयवंत पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण कमेटी डिप्टी चेयरमैन हेमा बेलानी, साथ ही बड़ी संख्या में कॉर्पोरेटर और स्थानीय नागरिक प्रोग्राम में मौजूद थे। इस प्रोग्राम के ज़रिए महिलाओं की उपलब्धियों को बढ़ावा देने और समाज को महिला एम्पावरमेंट का मैसेज देने की कोशिश की गई।

मिठी नदी की डीसिल्टिंग में 40% कटौती पर सवाल - स्थायी समिति में पार्षद तेजिंदर सिंह तिवाना ने उठाया हरकती का मुद्दा

मुंबई : मुंबई शहर की बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था से सीधे जुड़े मिठी नदी की डीसिल्टिंग के काम को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए स्थायी समिति सदस्य एवं नगरसेवक तेजिंदर सिंह तिवाना ने समिति की बैठक में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वर्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने मिठी नदी से गाद निकालने का काम लगभग 40% तक कम कर दिया है। पिछले वर्ष लगभग 2.67 लाख टन गाद निकालने का लक्ष्य था, जबकि इस वर्ष इसे घटाकर 1.65 लाख टन कर दिया गया है। साथ ही इस काम का खर्च भी ?48 करोड़ से घटाकर 29.5 करोड़ कर दिया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद तेजिंदर सिंह तिवाना ने कहा, 'अगर इस वर्ष 40% कम डीसिल्टिंग करने के बावजूद शहर में बाढ़ की स्थिति नहीं आती, तो पिछले कई वर्षों से इतने बड़े पैमाने पर गाद निकालने के अनुमान किस वैज्ञानिक सर्वे पर आधारित थे? इस विषय पर पिछले 10 वर्षों का पूरा विवरण देते हुए एक व्हाइट पेपर जारी किया जाना चाहिए।'

उन्होंने यह भी कहा कि यदि ठेकेदार टेंडर में भाग लेने से हिचक रहे हैं, तो महानगरपालिका को अपनी स्वयं की व्यवस्था बनाकर यह काम सीधे करना चाहिए तथा स्थायी रूप से 'Desilting Task Force' स्थापित करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ध्विद्‌तुर्मेंत ऐल्नब, उझए ट्रैकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और निकाली गई गाद का वजन सार्वजनिक किया जाए, ऐसी भी मांग की गई। इस दौरान स्थायी समिति के अध्यक्ष माननीय प्रभाकर शिंदे ने इस हरकती के मुद्दे को सुरक्षित रखते हुए प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा और मुंबई महानगरपालिका आयुक्त से पिछले दस वर्षों की डीसिल्टिंग पर एक व्हाइट पेपर सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की।

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओ के मनपा की फ्री बस सेवा

मंत्र भारत। भाईदंर

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस सर्विस में 22,055 महिलाओं ने फ्री यात्रा की। 08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ने पूरे दिन महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की सुविधा दी। इस पहल को शहर की महिलाओं से तुरंत रिस्पॉन्स मिला और इस साल कुल 22,055 महिलाओं ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बस सर्विस में फ्री यात्रा की। मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट के ज़रिए शहर के अंदर और शहर के बाहर ठाणे और बोरीवली के रूट पर रेगुलर बस सर्विस चलाई जा रही हैं, महापौर डिंपल विनोद मेहता ने कमिश्नर को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

के मौके पर महिलाओं के सम्मान में यह खास सुविधा देने के बारे में लिखा था। उसी के अनुसार महिलाओं के लिए यह खास सुविधा दी गई। मीरा भयंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के ज़रिए पिछले कुछ सालों से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा देने की परंपरा लगातार जारी है। इस पहल को हर साल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और देखा गया है कि महिलाओं में इस सुविधा को लेकर एक पॉजिटिव भावना पैदा हुई है। महिलाओं के सम्मान में लागू की गई इस पहल के ज़रिए, महिलाओं को सुरक्षित और आसान यात्रा की सुविधा देने और समाज में महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही, इस सुविधा का लाभ उठाने वाली शहर की सभी महिला यात्रियों के लिए, मेयर डिंपल मेहता, कमिश्नर राधाबिनोद ए. शर्मा (B.P.S.), डिप्टी मेयर ध्रुवकिशोर पाटिल और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हसमुख गहलोत ने महिलाओं का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि भविष्य में भी महिलाओं के सम्मान और सुविधा के लिए ऐसी जन-उन्मुख पहल लगातार आयोजित की जाएंगी।

मध्य रेल

सोलापुर मण्डल

विद्युत कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा क्रं :** सोला/क.वि./नि/2025/23R1। **कार्य का नाम :** सोलापुर मंडल के विद्युत टीआरडी भाग का कार्य के संबंध में दौंड-सोलापुर खंड में मलठन स्टेशन पर प्रत्येक दिशा में एक लंबी दूरी की लूप लाइन के प्रावधान। (पुनर्निविदा) **अनुमानित लागत :** ₹ 1,22,40,703.62। **बयाना राशि :** ₹ 2,11,200/-। **कार्य पुरा करने की अवधि :** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता :** 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय :** दि. 07.04.2026 को 15.00 बजे। EXP-10

टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

पश्चिम रेलवे

निर्माण कार्य

उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-1, पश्चिम रेलवे, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा निविदा क्रमांकः IND-UJN-SIMHASTHA-3 आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नाम :** सिंहस्थ 2028 के लिए चिंतामन गणेश स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन का निर्माण, यात्री सुविधाओं का निर्माण, प्लेटफॉर्म कार्य, प्लेटफॉर्म के लिए आवरण शेड, फुट ओवर ब्रिज का विस्तार, यार्ड ड्रेन, मशीन से कुचले हुए पत्थर के बैलेस्ट की आपूर्ति व फैलाव, मुख्य लाइन/लूप लाइनों तथा पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग के लिए ब्रॉड गेज ट्रैक का बिछाना एवं जोड़ना, पी-वे सामग्री का परिवहन, रेल की वेल्डिंग तथा अन्य संबंधित विविध कार्य आदि। **अनुमानित लागत :** 9,71,26,016.42 **ईएमडी :** 6,35,600/- **निविदा जमा करने की तिथि एवं समय :** 30.03.2026 को 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि :** 30.03.2026 को 15:30 बजे। निविदा की संपूर्ण जानकारी, पात्रता मानदंड सहित, ई-निविदा पोर्टल www.ireps.gov.in पर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण)-1, पश्चिम रेलवे, इंदौर के कार्यालय (प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने) के सूचना पट पर उपलब्ध है। 1206

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

देश का पहला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा महाराष्ट्र– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में सबसे मजबूत; 2029 तक 'ट्रिलियन डॉलर' का लक्ष्य

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य के विकास के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया है। महाराष्ट्र देश में आर्थिक रूप से मजबूत राज्य के रूप में खड़ा है और आने वाले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र देश का पहला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री फडणवीस वर्ष 2026-27 के बजट पर विधानसभा में हुई सामान्य चर्चा का जवाब दे रहे थे। बजट पर चर्चा में लगभग 84 सदस्यों ने भाग लिया। बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति, ऋण अनुपात, सिंचाई, बिजली, उद्योग, आधारभूत संरचना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया और यह भी उल्लेख किया कि जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया वह छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का दिन था।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बजट के माध्यम से राज्य को आगे ले जाने का प्रयास किया गया है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद महाराष्ट्र में वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास करने की क्षमता है। उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार ने लगातार वित्तीय अनुशासन बनाए रखा और उसी प्रकार इस बजट में भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। राज्य की प्रगति के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है और महाराष्ट्र ने ऑस्ट्रिया, थाईलैंड, नॉर्वे, फिलीपींस, वियतनाम और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले दो-तीन वर्षों में महाराष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 16 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले दस वर्षों में बढ़कर 51 लाख करोड़ रुपये हो गया है। स्थिर कीमतों पर राज्य की विकास दर 7.9 प्रतिशत और वर्तमान कीमतों पर 10.4 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति आय 3,17,800 रुपये से बढ़कर 3,47,903 रुपये हो गई है। देश की कुल जनसंख्या में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 9.5 प्रतिशत है, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य की हिस्सेदारी 14.3 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विदेशी निवेश, गैर-तेल निर्यात, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, बैंक जमा, बैंक ऋण वितरण और जीएसटी संग्रह में महाराष्ट्र देश में अग्रणी है। 'फॉरेस्ट ऑफ इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण में भी राज्य शीर्ष स्थान पर है।

अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति मजबूत

राज्य के ऋण के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण को आय के अनुपात में देखा जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 में राज्य की आय 16 लाख करोड़ रुपये थी और ऋण लगभग 3 लाख करोड़ रुपये था। अब आय 51 लाख करोड़ रुपये हो गई है और ऋण 9.32 लाख करोड़ रुपये है। राज्य का 'ऋण-से-जीडीपी' अनुपात लगभग 18.2 प्रतिशत है, जो 25 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है। गुजरात (15.3 प्रतिशत) और ओडिशा (13.1 प्रतिशत) को छोड़कर महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति कई राज्यों से बेहतर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह अनुपात 30 से 46 प्रतिशत के बीच है।

केंद्र से मिलने वाले निधि में बड़ा बढ़ोतरी

वर्ष 2013-14 में महाराष्ट्र को केंद्रीय करों में 16,588 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला था, जो 2025-26 में बढ़कर 87,903 करोड़ रुपये हो गया है। अनुदान भी 13,241 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 68,000 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त आयोग के समक्ष रखी गई मांग से राज्य को लगभग 90,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

पिछले दस वर्षों में राज्य के राजस्व संग्रह में भी भारी वृद्धि हुई है। यह 1.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 6.16 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की सीमा में रखना आवश्यक है और महाराष्ट्र में यह 2.78 प्रतिशत है। राजस्व घाटा भी 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखा गया है। वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा 41 हजार करोड़ रुपये था, जिसे अब घटाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली देने जैसी योजनाओं के बावजूद राज्य ने राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखा है।

विकास के लिए निवेश अधिक महत्वपूर्ण

वर्ष 2013-14 में राज्य का पूंजीगत व्यय 25,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यदि परासंस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो भी यह व्यय 1.17 लाख करोड़ रुपये है। इससे स्पष्ट है कि ऋण वृद्धि की तुलना में विकास के लिए निवेश अधिक बढ़ा है।

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

मुख्यमंत्री फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2029-30 तक महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 660 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और पिछले वर्ष में ही इसमें 55 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। इसी गति से विकास जारी रहा तो अगले पांच-छह वर्षों में यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनेगी जांच समिति– चंद्रकांतदादा पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कॉलेजों में फीस निर्धारण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की जाएगी, ऐसा उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में घोषणा की।

इस विषय पर सदस्य महेश शिंदे ने महत्वपूर्ण सुझाव रखा था, जबकि इस चर्चा में सदस्य प्रशांत बंब ने भी भाग लिया।

उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य में फीस निर्धारण के लिए फीस नियमन प्राधिकरण कार्यरत है। प्रत्येक कॉलेज के लिए पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समिति द्वारा स्वीकृत कुल खर्च की राशि को विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित कर फीस निर्धारित की जाती है और यह तीन वर्षों तक लागू रहती है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आठ लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की फीस का भार राज्य सरकार वहन कर रही है।

हालांकि कुछ कॉलेजों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोफेसरों का वेतन दिखाकर फीस बढ़ाई है जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं, अधूरे निर्माण कार्य का खर्च दर्शाया है या अन्य खर्चों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। यदि जांच में इस संबंध में बड़ा घोटाला सामने आता है तो विशेष जांच दल नियुक्त कर, प्राथमिकी दर्ज कर या आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मंत्री पाटिल ने स्पष्ट किया।

उन्होंने यह भी बताया कि इस जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग का एक उपसचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

प्रभावित किसानों को राहत ;जलगांव जिले के लिए 15.77 करोड़ रुपये की सहायता– मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई, दिनांक 11 : प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल शासन निर्णय जारी कर जलगांव जिले के लिए लगभग 15 करोड़ 77 लाख रुपये की सहायता मंजूर की है। राज्य में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान किसानों को लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

इसके साथ ही खरीफ मौसम के दौरान राज्य के 1 करोड़ 2 लाख किसानों की 79 लाख 83 हजार 581 हेक्टेयर भूमि को हुए नुकसान के लिए लगभग 15 हजार 817 करोड़ रुपये की सहायता देकर किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है, ऐसी जानकारी राहत व पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने दी।

जलगांव जिले के रावेर और यावल तालुकों में बेमौसम बारिश के कारण कृषि फसलों को हुए नुकसान के संबंध में सदस्य अमोल जावले ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था।

राहत व पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने बताया कि सहायता प्रदान करते समय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के मानकों के अनुसार सहायता दी जाती है। विशेष मामले के रूप में मुआवजा देने की सीमा 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 3 हेक्टेयर कर दी गई है। साथ ही बाढ़ या फसल डूबने से नुकसान झेलने वाले किसानों को भी सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने यह भी कहा कि सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर रिपोर्ट मंगवाकर संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई तेज- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा करने वाले 38 लाख मामलों से जुर्माने के रूप में 227 करोड़ रुपये वसूले गए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल अपने सम्मानित यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के तहत, अपने पूरे नेटवर्क में अनधिकृत और बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए अपने उपायों को तेज कर रहा है।

गहन और व्यवस्थित टिकट जाँच अभियानों के माध्यम से, मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26

मध्य रेल की समर्पित टिकट जाँच टीमों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान बिना टिकट यात्रा कर रहे, अनुचित या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 37.99 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 34.60 लाख यात्रियों को पकड़ा गया था, जो लगभग 10इ की वृद्धि है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के दौरान जुर्माने के रूप में रिकॉर्ड 227.03 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 185.62 करोड़ रुपये वसूले गए थे, जो 22इ से अधिक की वृद्धि है।

फरवरी 2026ङ के दौरान, मध्य रेल की टिकट जाँच टीमों ने बिना टिकट यात्रा कर रहे, गलत या अमान्य यात्रा प्राधिकरण वाले 3.65 लाख यात्रियों को पकड़ा, जबकि फरवरी 2025 में यह संख्या 3.32 लाख थी, जो लगभग 10इ की वृद्धि दर्शाती है।

फरवरी 2026 में अपराधियों से जुर्माने के रूप में 23.27 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि फरवरी 2025 में यह राशि 18 करोड़ रुपये थी, जो लगभग 30इ की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से फरवरी 2026) के लिए मंडलवार विवरणः

बिना टिकट/वैध टिकट के यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों और उनसे वसूल की गई जुर्माने की राशि इस प्रकार हैः

मुंबई मंडल : 16.16 लाख मामलों से 71.32 करोड़ रुपये,

भुसावल मंडल : 8.94 लाख मामलों से 75.29 करोड़ रुपये,

पुणे मंडल : 4.31 लाख मामलों से 27.14 करोड़ रुपये,

नागपुर मंडल : 4.00 लाख मामलों से 24.93 करोड़ रुपये,

सोलापुर मंडल : 2.30 लाख मामलों से 10.53 करोड़ रुपये और

मुख्यालयः 2.28 लाख मामलों से 17.82 करोड़ रुपये

मध्य रेल अनधिकृत यात्रा का पता लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाता है, जिसमें स्टेशन चेक, एम्बुश चेक, फोर्ट्रेस चेक, गहन चेक और मेगा टिकट चेकिंग अभियान शामिल हैं। ये अभियान सभी मंडलों में चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों और स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ मुंबई और पुणे मंडल में चलने वाली उपनगरीय ट्रेनों पर भी लागू हैं।

मध्य रेल यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं द्वारा जारी वैध टिकटों के साथ यात्रा करें, या रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटरों से, या एटीवीएम के माध्यम से, या वेबसाइट http://www.irctc.co.in के माध्यम से टिकट बुक करें।

यात्री अपने मोबाइल फोन पर रेल वन ऐप डाउनलोड करके भी टिकट बुक कर सकते हैं।

मध्य रेल यात्रियों से यह भी अनुरोध करता है कि वे फर्जी टिकट बनाने/प्राप्त करने और उन पर यात्रा करने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग न करें।

यह अपराध भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 के तहत दंडनीय है, जिसमें जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।

रेलवे बिना टिकट यात्रा के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति को दोहराता है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को आरामदायक और सम्मानजनक यात्रा मिले।

अभिनय और संगीत में आवाज का महत्व समझना जरूरी : पद्मश्री प्रो. वामन केंद्रे

बृहन्मुंबई महानगरपालिका के संगीत एवं कला अकादमी द्वारा संगीत शिक्षकों के लिए प्रायोगिक व्याख्यान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई : आवाज मनुष्य को मिला एक अनमोल उपहार है। संगीत शिक्षकों को आवाज और ध्वनि के बीच का अंतर पहचानना आना चाहिए। संगीत सिखाते समय आवाज के उतार-चढ़ाव को संतुलित रखना और सार्थक संवाद करना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आवाज में सकारात्मकता होती है, तो संवाद सीधे दिल तक पहुंचता है। इन शब्दों में प्रसिद्ध नाटककार, निर्देशक और पद्मश्री प्रो. वामन केंद्रे ने संवाद के महत्व को स्पष्ट किया।

पद्मश्री प्रो. वामन केंद्रे बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग की संगीत एवं कला अकादमी (संगीत विभाग) द्वारा आयोजित नाट्य विषय पर प्रायोगिक व्याख्यान में बोल रहे थे। यह व्याख्यान मंगलवार (10 मार्च 2026) को करी रोड स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में आयोजित किया गया।

इस व्याख्यान के दौरान प्रो. केंद्रे ने कुछ संगीत शिक्षकों से आवाज और चेहरे के हावभाव का प्रदर्शन भी करवाया। इसके माध्यम से उन्होंने उपस्थित संगीत शिक्षकों को संवाद कौशल और शारीरिक भाषा के सही समन्वय के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

इस कार्यक्रम में संगीत अकादमी की सलाहकार समिति की सदस्य श्रीमती श्रुति सडोलीकर-कटकर, संगीत अकादमी की प्राचार्या श्रीमती शिवांगी दामले सहित शिक्षा विभाग के अनेक शिक्षक और संगीत शिक्षक उपस्थित थे।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक प्रो. केंद्रे ने अपने प्रभावशाली अंदाज में अभिनय और संगीत में आवाज के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि आवाज केवल ध्वनि नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवंत व्यक्तित्व की पहचान है। आवाज की सकारात्मकता को पहचानना जरूरी है। यदि दिन की शुरुआत सकारात्मक संवाद से की जाए तो पूरे दिन के कार्यों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके विपरीत नकारात्मक संवाद लोगों के साथ संबंधों को कमजोर कर देता है।

उन्होंने बताया कि दैनिक कार्यों के दौरान अक्सर तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन सकारात्मक संवाद कौशल होने पर इस तनाव से आसानी से निपटा जा सकता है। आवाज और संवाद के महत्व को समझाते हुए प्रो. केंद्रे ने संगीत शिक्षकों से कई प्रकार के प्रदर्शन भी करवाए। इन प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने बताया कि आवाज के उतार-चढ़ाव, स्वर की मधुरता और चेहरे के भाव हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आवाज की विशेषताओं को पहचानकर उस पर काम करना चाहिए। सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि संवाद करते समय चेहरे पर मुस्कान, सकारात्मक शारीरिक भाषा और स्पष्ट शब्दों का उपयोग संवाद को अधिक प्रभावी बनाता है।

इस कार्यशाला में उन्होंने मंच पर आए शिक्षकों को आवाज के उतार-चढ़ाव, उसके सूक्ष्म स्वर, उच्चारण और चेहरे के भावों पर ध्यान देकर आवाज की मधुरता बनाए रखने के तरीके भी बताए। इस अवसर पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका की सभी संगीत और कला विद्यालयों के शिक्षक उपस्थित थे। उपस्थित संगीत शिक्षक इस कार्यशाला की जानकारी अपने विद्यार्थियों को भी देंगे।

उर्वरक बिक्री में अनियमितताएं ; दोषी विक्रेताओं के लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित करने का निर्णय– कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

उर्वरक की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के लाइसेंस 15 दिनों के बजाय छह महीने के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरने ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस विषय पर सदस्य राजेश पवार ने प्रश्न उठाया था। इस चर्चा में सदस्य नाना पटोले, जयंत पाटिल और अभिजीत पाटिल ने भाग लिया।

नांदेड़ जिले के नायगांव तालुका में उर्वरकों की कीमत बढ़ने और उपलब्धता को लेकर शेतकरी पुत्र संघर्ष समिति द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जिला कृषि अधिकारी ने 5 दिसंबर 2025 को कृषि विकास अधिकारी (जिला परिषद) की अध्यक्षता में एक उड़नदस्ता दल गठित किया। इस दल ने 8 दिसंबर 2025 को नायगांव में रासायनिक उर्वरक बिक्री के सात केंद्रों की जांच की।

जांच में पाया गया कि चार विक्रेताओं ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचा, जबकि तीन विक्रेताओं ने स्टॉक होने के बावजूद किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराया। इसलिए सभी सात विक्रेताओं के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस मामले में कृषि आयुक्त को प्रारंभिक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और जांच की गई। इनमें से 1,543 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए, 1,174 लाइसेंस रद्द किए गए और 2,956 बिक्री केंद्रों को बिक्री बंद करने के आदेश दिए गए।

इसके अलावा 2,149 उत्पादों की जांच की गई और 52,910 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 3,462 नमूने नकली पाए गए और लगभग 3,100 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार जब्त किया गया। इन मामलों में 147 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और किसानों को उर्वरक की कोई कमी नहीं होगी।

दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कृषि मंत्री भरने ने कहा।

उन्होंने बताया कि राज्य में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने के लिए बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से 5 मार्च 2026 तक पूरे राज्य में 1,14,860 बिक्री केंद्रों की

सम्पादकीय

डिजिटल युग में सज्जनता की नई तस्वीर केवल लाइक्स के लिए है आपकी मदद कैमरे के सामने परोपकार

मानव सभ्यता का अतीत जितना संघर्षों का इतिहास है, उतना ही परोपकार और सहानुभूति से भी भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का भाव होता है, जो उसे दूसरों के दुख में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। यही भाव समाज को जोड़ता है, मनुष्यता को अर्थ देता है और जीवन को गरिमा प्रदान करता है।

मगर आधुनिक समय में, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, इस करुणा की अभिव्यक्ति के रूप और उद्देश्य में एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सहायता एक 'दिखावे' में भी तब्दील हो रही है। इस प्रवृत्ति में उपकार की छवियां कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। क्या यह सचमुच सेवा है या सेवा के आवरण में स्वार्थ और आत्मप्रचार का एक नया रूप है?

भारतीय संस्कृति में सेवा को एक उच्चतम नैतिक कर्तव्य माना गया है। संत कबीर, महात्मा गांधी और अन्य विचारकों ने निस्वार्थ सेवा को मनुष्य का धर्म बताया है। सेवा का आदर्श यही रहा है कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के किया जाए। उसमें न अहंकार हो, न प्रदर्शन। सहायता का अर्थ किसी की पीड़ा को कम करना है, न कि उस पीड़ा को सार्वजनिक करके स्वयं को महान दिखाना।

मगर आज अक्सर कोई व्यक्ति किसी वंचित, गरीब या असहाय की मदद करता है, तो कैमरा तुरंत सामने आ जाता है। सहायता पाने वाला व्यक्ति एक 'दृश्य' बन जाता है, जो 'लाइक, शेयर और कमेंट' की दुनिया में फैलता है। सेवा का भाव पीछे छूट जाता है और इसके बदले 'मान्यता की लालसा' आ जाती है।

सोशल मीडिया ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह संवाद का माध्यम होने के साथ-साथ आत्म-प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच भी बन गया है। अब परोपकार केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि 'डिजिटल प्रतिष्ठा' पाने का साधन बन गया है। गरीब को भोजन कराना, जरूरतमंद को कपड़े या औषधि देना, या किसी वृद्ध की मदद करना–इनमें कैमरे की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है।

इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि अन्य लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष भी है। लाभार्थी की निजता और अस्मिता अक्सर अनदेखी हो जाती है। जब किसी की तस्वीरें बिना अनुमति साझा की जाती हैं, तो वह व्यक्ति एक 'वस्तु' बन जाता है। उसका आत्मसम्मान ठेस पहुँचता है और अस्मिता पर आघात होता है।

सेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें संवेदनशीलता हो। सहायता करते समय हमें सोचना चाहिए कि क्या हम व्यक्ति की स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसकी पीड़ा को 'कंटेंट' या प्रचार सामग्री में बदल रहे हैं? यदि हां, तो यह सेवा नहीं, बल्कि शोषण का एक रूप है।

कई बार सरकारें और संस्थाएं कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करने के लिए लाभार्थियों की तस्वीरें सार्वजनिक करती हैं। प्रचार जरूरी हो सकता है, लेकिन इसमें संतुलन और संवेदनशीलता होनी चाहिए। लाभार्थी की निजता का सम्मान अनिवार्य है।

इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से होगा। सेवा का अर्थ गरिमा के साथ मदद करना है। यदि फोटो लेना आवश्यक हो, तो लाभार्थी की स्पष्ट अनुमति ली जाए। बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों में विशेष सावधानी रखी जाए।

अंततः उपकार की सच्ची छवि कैमरे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की मुस्कान में दिखाई देती है जिसकी मदद की गई है। वह मुस्कान ही सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे सोशल मीडिया पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। सेवा करते समय हमारी करुणा और सहानुभूति केवल 'छवियों' तक सीमित न रह जाए, बल्कि वास्तविक जीवन में सम्मान और संवेदना का रूप ले। तभी उपकार की छवियां सचमुच सार्थक बन पाएंगी।

वैश्विक राजनीति के कुशल नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी

संकटों के दौर में उभरती भारत की शक्ति और विपक्ष की सीमित दृष्टि

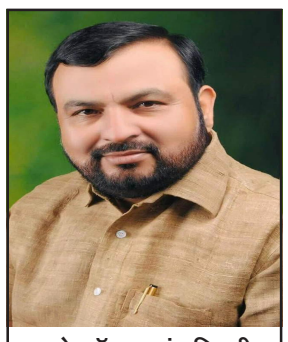

प्रो. डॉ. दयानंद तिवारी (शिक्षाविद्, चिंतक एवं सामाजिक विश्लेषक)

आज का विश्व एक अस्थिर दौर से गुज़र रहा है। कहीं युद्ध की विभीषिका है, कहीं आर्थिक मंदी का भय, तो कहीं ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियाँ वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक संतुलन को गहराई से झकझोर दिया है। यूरोप और अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ भी महँगाई, ऊर्जा संकट और बेरोज़गारी आदि की समस्याओं से जूझ रही हैं।

ऐसे समय में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर और मजबूत दिखाई देती है। यह स्थिति संयोग नहीं है, बल्कि दूरदर्शी नीतियों, रणनीतिक निर्णयों और सशक्त नेतृत्व का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक संतुलन की जिस नीति को अपनाया है, उसने देश को वैश्विक संकटों के बीच भी एक भरोसेमंद और उभरती शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

जैसा कि कहा गया है
'दूरदर्शी नेतृत्व संकटों को अवसर में बदल देता है।'

आर्थिक शक्ति का उभार और विकास का नया अध्याय

विश्व आर्थिक अस्थिरता के बावजूद भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ भी भारत की विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान व्यक्त कर रही हैं।

मोदी सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढाँचे के विकास पर अभूतपूर्व निवेश हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, आधुनिक एक्सप्रेसवे, तेज़ गति की रेल व्यवस्था और नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण भारत के आर्थिक ढाँचे को नई गति दे रहा है। इससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन के नए द्वार खुले हैं।

'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों ने देश के औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर है।

'सशक्त अर्थव्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।'

ऊर्जा सुरक्षा और व्यावहारिक कूटनीति

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल हुई। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएँ इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुईं। ऐसे समय में भारत ने व्यावहारिक और संतुलित नीति अपनाकर ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखा।

भारत ने एक ओर आवश्यक तेल और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल ने भारत को

ऊर्जा कूटनीति के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया है।

यह नीति बताती है कि भारत केवल वर्तमान संकट से निपटने की रणनीति नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य की ऊर्जा संरचना भी तैयार कर रहा है।

सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती

आज के वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने से भारत की सामरिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधुनिक हथियार प्रणालियाँ, रक्षा अनुसंधान और तकनीकी नवाचार भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं।

सीमा सुरक्षा के साथ-साथ सेना, नौसेना और वायुसेना का आधुनिकीकरण भारत की वैश्विक सामरिक प्रतिष्ठा को भी मजबूत कर रहा है।

डिजिटल क्रांति और तकनीकी भारत

डिजिटल तकनीक आज किसी भी राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। भारत में डिजिटल क्रांति ने प्रशासन, व्यापार और समाज को नई दिशा दी है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली, आधार आधारित सेवाएँ और ऑनलाइन शासन व्यवस्था ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। भारत आज विश्व के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क में से एक का संचालन कर रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी भविष्य के तकनीकी भारत की नींव रख रही है।

शिक्षा सुधार और नई पीढ़ी का निर्माण

नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है।

शोध, नवाचार और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन देकर युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा के विस्तार से शिक्षा की पहुँच और व्यापक हुई है।

रोजगार, स्टार्टअप और युवा शक्ति

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा जनसंख्या है। स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने से लाखों युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेवा क्षेत्र और तकनीकी उद्योग के विस्तार ने भारत को रोजगार सृजन के नए केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

विपक्ष की नकारात्मक राजनीति

दुर्भाग्य से देश की राजनीति में कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय उपलब्धियों को स्वीकार करने के बजाय केवल आलोचना की राजनीति करते हैं। जब देश वैश्विक मंचों पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, तब भी कुछ राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण विकास की उपलब्धियों को नकारने का प्रयास करते हैं।

विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी होता है। परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी राजनीति का आधार राष्ट्रहित नहीं, बल्कि तात्कालिक राजनीतिक लाभ है।

जब विश्व भारत की प्रगति को स्वीकार कर रहा है, तब अपने ही देश में उसके महत्व को कम करके आँकना लोकतांत्रिक विमर्श की परिपक्वता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

अंततः आज जब विश्व अनेक संकटों से घिरा हुआ है, तब भारत की स्थिरता और प्रगति विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रही है। आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण, संतुलित कूटनीति, तकनीकी प्रगति, शिक्षा सुधार और रोजगार सृजन–इन सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों ने भारत को एक सशक्त और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल विकास की गति ही नहीं बढ़ाई, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी प्रभावी भूमिका स्थापित की है।

सच ही कहा गया है कि...
'जब नेतृत्व राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखता है, तब इतिहास नए अध्याय लिखता है।'

अंत में यही कहूंगा कि..
संकट के बीच खड़ा, अडिग भारत महान,
नीति, श्रम और संकल्प से बढ़ता उसका मान।
दूरदर्शी नेतृत्व से जग में फैला विश्वास,
नवयुग का भारत रचता इतिहास।

हड्डियां जलाने वाले गोले दागे, एक पायलट की तलाश में लेबनान के कब्रिस्तान क्यों खोद रहा इजरायल?

कुछ ही दिन पहले ईस्टर्न लेबनान में देर रात एक ड्रामेटिक मिशन के दौरान इजराइल की स्पेशल फोर्सेस ने एक गांव में तलाशी शुरू की। किसी आम जगह या घर की नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान की। मिशन था 40 साल से लापता एक इजराइली पायलट की कब्र और उनके अवशेष खोजना। पर इजराइल का ऑपरेशन रातोंरात असफल हो गया। ऑपरेशन के दौरान इजराइयली कमांडोज़ और हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ-साथ कुछ लोगों के बीच गोलीबारी हो गई। इसके बाद इजराइली लड़ाकू विमानों ने इलाके पर हवाई हमले किए जिनमें कई लोगों की मौत हो गई। लेबनीज़ आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस लड़ाई में तीन लेबनानी सैनिक और बेकावे वैली के 41 रेजिडेंट्स मारे गए हैं। वहीं इजराइली सैनिकों के घायल होने की कोई खबर अब तक नहीं मिली है।

पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका ईरान युद्ध जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे उसका अमानवीय पक्ष सामने आ रहा है। अब लेबनान के मानवाधिकार संगठनों ने गंभीर आरोप लगाया है कि इजराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर कस्बे के रिहायशी इलाके पर सफेद फॉस्फोरस के गोले दागे, जिससे घरों और कारों में आग लग गई और लोग झुलस गए। संगठनों ने वीडियो और फोटो जारी कर दावा किया कि 3 मार्च के हमले में हवा में फटने वाले सफेद फॉस्फोरस के गोले इस्तेमाल किए गए, जिनसे जलते कण बड़े इलाके में फैल गए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 7 तस्वीरों को सत्यापित किया है, जिनमें रिहायशी इलाके के ऊपर गोले फटते दिखाई देते हैं। संगठन ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ है।

सफेद फॉस्फोरस बेहद ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तुरंत जल उठता है। जलने पर इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और हड्डी तक जला देता है। हवा में फटने पर यह 125 से 250 मीटर के दायरे में सैकड़ों जलते कण फैला देता है। इससे त्वचा और मांस गंभीर रूप से जल सकते हैं, जहरीला धुआं फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और घर, खेत व वाहन में आग लग सकती है।

अमेरिका पर 2004 में इराक के फलूजा युद्ध में सफेद फॉस्फोरस इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे। इजराइल ने 2008 से 2009 गाजा युद्ध में इसके इस्तेमाल की बात मानी थी। 2023 में भी इजराइल पर गाजा और लेबनान में भी ऐसे हमलों के आरोप लग चुके हैं। 1980 में संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल-छ्छ के तहत आग लगाने वाले हथियारों के इस्तेमाल पर कड़े नियम बने। आबादी वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग प्रतिबंधित है। सफेद फॉस्फोरस पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन नागरिक इलाकों में इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

लेबनीज़ आर्मी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 10:00 बजे दो इजराइली हेलीकॉप्टर सीरिया लेबनान सीमा पर बेकावे वैली में स्थित नबीचित और क्राइबे कस्बों के पास लैंड हुए। जिनसे इजराइली सैनिकों को नीचे उतारा गया। इसके बाद सैनिक नबीचित के कब्रिस्तान में पहुंचे और एक कब्र की खुदाई शुरू कर दी। उन्हें यहां पर शक हुआ था कि वहां 1986 में लेबनान में लापता हुए इजराइली पायलट रॉन अराद के अवशेष दफन मिल सकते हैं। कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एक कब्र के पास ताजा खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। उस जगह थोड़ी देर के लिए खुदाई की गई थी और फिर इजरायली फोर्सेस वहां से वापस लौट गई। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इजराइयली हेलीकॉप्टर इलाके में उतरे तो लेबनी सेना ने इस घुसपैठ का पता लगा लिया और हेलीकॉप्टरों के ऊपर फ्लेयर डाली। इसके बाद इजराइयली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई।

आईडीएफ यानी कि इजराइयली डिफेंस फोर्सेस ने इस दौरान शहर पर कम से कम 40 हवाई हमले किए। ऑन ग्राउंड इजराइली सैनिकों, स्थानीय लोगों और हिजबुल्ला के बीच लड़ाई चलती रही जो सुबह करीब 3:00 बजे तक जारी रही। द गार्डियन की एक रिपोर्ट बताती है घटना के वीडियो में लगातार गोलीबारी दिखाई दी जिसमें आसमान में ट्रेसर बुलेट साफ नजर आ रही थी। साल 1986 में इजराइल और लेबनान के उग्रवादी संगठन हज़बुला के बीच लड़ाई हुई थी और इसके दौरान लेबनान के ऊपर से उड़ता हुआ एक इजराइली एयरक्राफ्ट एफ4 फैंटम टू फाइटर बम्बर मार गिराया गया था। इस एयरक्राफ्ट के नेविगेटर रॉन अराध थे और पायलट यशाई अविराम। अविराम सेफ रिजेक्ट हो गए थे। जिन्हें बाद में इजरयली फोर्सेस ने रेस्क्यू भी कर लिया था। पर इस घटना के बाद अराध लापता हो गए।

कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद रॉन को शिया मिलिशिया अमाल मूवमेंट ने पकड़ लिया और बाद में हिजबुल्ला को सौंप दिया गया था। लेट 1980 के बाद से उनके जिंदा होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। 2004 में इजराइल के गवर्नमेंट कमीशन ने कंक्लूड भी किया था कि रॉन अराध की मौत मिड 1990 में हो चुकी थी। इसके बावजूद इजरयली सरकार उनके अवशेष ढूंढने की कोशिश करती रही है। 2021 में उस समय के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने कहा था कि इजराइली इंटेलिजेंस ने ईरान के एक जनरल को सीरिया से अगवा किया था ताकि अराद के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेबनान रीजन में यह आमतौर पर माना जाता है कि विमान दुर्घटना के कुछ समय बाद रॉन अराध की मौत हो गई थी और उन्हें बेका वैली के किसी इलाके में दफन कर दिया गया था। हालांकि उनकी कब्र की सही जगह कहां है? आज तक यह कंफर्म नहीं हो पाया है।

यूक्रेन तो अमेरिका-इजरायल से भी बड़ा खिलाड़ी निकला, ईरान की मार से कतर, यूएई और सऊदी अरब को बचाने भेजे अपने मिलिट्री एक्सपर्ट्स

एक ऐसा शब्द जो दुनिया की तस्वीर बदल देता है। सुपर पावर जब भी यह शब्द सुनते हैं, तो जहन में अमेरिका, रूस, चीन का नाम आता है। लेकिन अब ऐसी कहानी जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका रही है। वो देश जो महज कुछ साल पहले तक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। आज उसी देश को दुनिया का अगला मिलिट्री सुपर पावर कहा जा रहा है। वो देश यूक्रेन है। दरअसल, मध्य-पूर्व में दशकों बाद अमेरिकी सैन्य ताकत की सबसे बड़ी तैनाती के बीच अमेरिका-ईरान टकराव का एक दिलचस्प और थोड़ा विडंबनापूर्ण पहलू सामने आया है। इस संघर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने चुपचाप अपना लो-कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम (लुकास) मैदान में उतारा। एक ऐसा एक-तरफ़ा हमला करने वाला ड्रोन, जिसकी अवधारणा उसी सस्ती ड्रोन तकनीक से मिलती-जुलती है, जिसे ईरान कई दशकों से विकसित करता रहा है। ईरान के 'शाहेद' ड्रोन आज उसके सबसे अहम हवाई हथियारों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी तकनीक की प्रेरणा कभी इज़राइल में विकसित ड्रोन प्रणालियों से मिली थी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और सीमित संसाधनों ने ईरान को मजबूर किया कि वह इन्हीं ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने स्वदेशी सैन्य कार्यक्रम का केंद्र बना दे। इनका मकसद पश्चिमी रक्षा प्रणालियों को सीधे चुनौती देकर हराना नहीं, बल्कि लगातार हमलों के जरिए उन्हें थका देना और उनके संसाधन खत्म करना है। इसी श्रृंखला का शुरुआती मॉडल शाहेद-131 था, जिसने सितंबर 2019 में सऊदी अरब की एक तेल रिफाइनरी पर हुए हमले के दौरान पहली बार बड़े पैमाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और तभी से दुनिया को यह अहसास होने लगा कि सस्ते लेकिन घातक ड्रोन युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। जो शुरुआत में केवल एक सैन्य मजबूरी का उपाय था, वही समय के साथ एक वैश्विक हथियार बन गया। सबसे पहले ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे यमन में हौती विद्रोहियों ने इन ड्रोन का इस्तेमाल किया और बाद में रूस ने भी यूक्रेन युद्ध में इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया। इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ईरान को पुतिन का सहयोगी तक कहा, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ रूस को शाहेद ड्रोन दिए बल्कि उन्हें बनाने की तकनीक भी उपलब्ध कराई।

ब्रिटानिका के अनुसार सुपर पावर वो राष्ट्र है जिसे दुनिया की मंच पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जिसके सहयोग के बिना दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या हल नहीं हो सकती। इतिहास में देखें तो अब तक केवल दो देशों को निर्विवाद सुपर पावर का दर्जा मिला है। अमेरिका और सोवियत संघ। आज भले ही रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को कुछ मापदंडों पर सुपर पावर कहा जाए लेकिन अमेरिका अभी भी सबसे ऊपर है। लेकिन रूस से बीते चार बरस से जंग ले रहा छोटा सा मुल्क यूक्रेन अभ चर्चाओं में है। यूक्रेन का कान्फिडेंस कहे या सुपरपावर बनने की दिशा में कदम की अब उसने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की रक्षा के लिए ड्रोन विशेषज्ञों और इंटरसेप्टर ड्रोन की एक विशेष टीम भेजी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका ने हाल ही में सुरक्षा सहायता के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही अमेरिका की ओर से मदद मांगी गई, यूक्रेन ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपने विशेषज्ञों को भेजने का फैसला किया।

राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि वे ईरानी ड्रोन को मार गिराने की विशेषज्ञता साझा करेंगे। यूक्रेन को रूस द्वारा दागे जाने वाले ईरानी डिज़ाइन के शाहेद हमलावर ड्रोनों के रात्रिकालीन हमलों को भेजे गए एक ऑडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा कि समझौतों के अनुसार, हमने जिन पहले तीन देशों को ये ड्रोन भेजे हैं, वे हैं कतर,

संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। उन्होंने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर शाहेद हमलों को मार गिराने के मामले में, आज केवल यूक्रेनी अनुभव ही वास्तव में मददगार साबित हो सकता है।' उनका इशारा रूस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी डिज़ाइन के ड्रोनों की ओर था। उनके संचार सलाहकार ने पत्रकारों को यह भी बताया कि यूक्रेनी विशेषज्ञों को जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ज़ेलेंस्की ने खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों से यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर के बदले में बेहद जरूरी हवाई रक्षा मिसाइलें सौंपने का आह्वान किया है।

पहलाः ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सैन्य ताकत तैनात करने की क्षमता। अमेरिका के पास दुनिया भर में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। 11 परमाणु संचालित विमान वाहक पोत हैं और हजारों विमान व टैंकर हैं। अब यूक्रेन की बात करें तो यह वो देश है जिसकी नौसेना को 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में रूसी आक्रमण के दौरान लगभग नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस सूडान, माली और ईरान तक सक्रिय हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुडानोव के शब्दों में हमारा मिशन है रूसी युद्ध अपराधियों को दुनिया में कहीं भी नष्ट करना। सूडान के गृह युद्ध में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और जमीनी अभियान चलाए हैं। रूस के वागनर ग्रुप के भारी के सैनिकों के खिलाफ भी यूक्रेन ने मोर्चा खोला है। यह है यूक्रेन का ग्लोबल फुटप्रिंट और यह दिन-बदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहां यूक्रेन ने समुद्र में सबसे बड़ा धमाका किया है।

समुद्री युद्धः 2022 में जब रूस ने हमला किया तब यूक्रेन के पास एक छोटी कमजोर नौसेना थी। रूस का ब्लैक सी फ्लट सैकड़ों युद्ध पोतों से लैस था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूक्रेन इसे चुनौती दे सकता है। लेकिन यूक्रेन ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जिसने दुनिया के सैन्य इतिहास की दिशा बदल दी। नेवल ड्रोंस समुद्री ड्रोन। मगरा वी5 यह एक 18 फुट लंबा कार्बन फाइबर का बना समुद्री ड्रोन है। इसकी कीमत महज 2.5 से 3 लाख है। लेकिन यह उन युद्धपोतों को नष्ट करने में सक्षम है जिनकी कीमत अरबों डॉलर है। मई 2023 में तीन मगरा वी 5 ड्रोनों ने रूस के 4000 टन के इवान खुर्स जासूसी जहाज पर हमला किया जो यूक्रेन से सैक्ड़ों मील दूर था। फरवरी 2024 में मगरा वी5 ने इतिहास रच दिया। यह दुनिया का पहला नेवल ड्रोन बना जिसने दुश्मन के युद्धपोथ को डुबोया। रूस का इवानोवेट्स गाइडेड मिसाइल कारवेबेट और सेज़ार कुनिकोफ लैंडिंग शिप दोनों को इसने तबाह किया। एक साल में मगरा वी5 ने आठ रूसी युद्धपोत नष्ट किए। छह को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कुल नुकसान ऋ0 करोड़ डॉलर से ज्यादा। 2025 के अंत तक कम से कम 20 रूसी युद्धपोत इसका शिकार बन चुके थे।

समुद्र के बाद आसमानः एफपीवी का कामकाजे ड्रोंस ने जमीनी युद्ध की पूरी तस्वीर बदल दी। टैंक कॉलम्स जो कभी युद्ध में अजय माने जाते थे। अब यूक्रेनी एफपीवी ड्रोंस के सामने असहाय है।

ऑपरेशन स्पाइडर वेबः यूक्रेन ने एक साथ पांच रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। साइबेरिया जितनी दूर तक।

नष्ट हुए रूस के स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बमबर्स, ट्रांसपोर्ट और एक इवक्स टाइप रिकनेसेंस एयरक्राफ्टः यह हमला हुआ सस्ते क्वाडकोप्टर ड्रोंस से। इन ड्रोनों के पुरजे रूस में चुपके से स्मगल किए गए। वहां उन्हें असेंबल किया गया।

युद्ध के मैदान में सस्ते लेकिन बड़े पैमाने पर किए गए ड्रोन हमलों की सफलता से अमेरिका भी चौंक गया। इसके बाद अमेरिका ने गुप्त रूप से शाहेद-136 ड्रोन को हासिल कर उनका तकनीकी विश्लेषण करने की कोशिश की। इन नमूनों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझा गया और उनके आधार पर प्रशिक्षण के लिए प्रतिरूप तैयार किए गए, जिन्हें बाद में विकसित करके मौजूदा लुकास ड्रोन बेड़े का रूप दिया गया। इस कार्यक्रम की रफ्तार भी बेहद तेज रही। लॉन्च के महज़ पांच महीनों के भीतर पेंटागन ने मध्य-पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को लुकास ड्रोन से लैस कर दिया। यहां तक कि अरब सागर के इलाके में एक युद्धपोत से इन्हें समुद्र से लॉन्च करने की क्षमता का भी सफल परीक्षण किया गया।

28 फरवरी को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि लुकास ड्रोन का पहली बार वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन जमीन से लॉन्च किए गए थे और इन्हें 'स्कॉर्पियन स्ट्राइक' नामक अमेरिकी टास्क फोर्स ने संचालित किया, जिसे दिसंबर 2025 में खास तौर पर ईरान की ड्रोन रणनीति का जवाब देने के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि इन लुकास ड्रोन का इस्तेमाल 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में भी किया गया था, जहां अमेरिकी मिशन का लक्ष्य देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ना था। लेकिन ईरान के खिलाफ इनका आधिकारिक युद्धक इस्तेमाल एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। असल में यह सिर्फ एक नया हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी हवाई युद्ध की रणनीति में बदलाव का प्रतीक है।

मां-भाई बने जल्लाद

बेटी के प्रेम संबंधों से थे नाराज, गला रेतकर की हत्या और प्रेमी पर लगाया आरोप

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक युवती की संदिग्ध मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जिसे पहले हत्या और दुष्कर्म का मामला समझा जा रहा था, वह अंततः ऑनर किलिंग (सम्मान के नाम पर हत्या) निकला। समाज में बदनामी के डर से एक मां और भाई ने मिलकर अपनी ही बेटी की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी मां अफसाना और भाई अफसार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र की है। करीब एक सप्ताह पहले गांव से दूर चने के खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। मृतका के गले और चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे। शुरुआत में परिवार ने गांव के ही सुनील यादव नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झांसा देकर रेप किया और फिर हत्या कर दी।

पुलिस जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि युवती का सुनील यादव के साथ प्रेम प्रसंग था। युवती ने पहले भी इस रिश्ते को लेकर विवाद होने पर 25 फरवरी को रेलवे ट्रैक पर सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन तब आरपीएफ ने उसे बचा लिया था। इसके बाद परिवार के दबाव में उसने सुनील पर रेप का केस भी दर्ज कराया था।

पुलिस के मुताबिक, परिवार को डर था कि बेटी की वजह से समाज में उनकी बहुत बदनामी होगी। बीते रविवार की रात जब घर के सब लोग सो गए, तब युवती चुपके से घर से निकली। पीछे से उसकी मां और भाई भी पहुंच गए। गुस्से और नफरत में आकर दोनों ने मिलकर युवती की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। उनकी योजना इस हत्या का दोष प्रेमी सुनील यादव पर मढ़ने की थी, ताकि वह जेल चला जाए और उनकी बदनामी का दाग भी मिट जाए।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। उन्हें लगा था कि पुलिस पहले से दर्ज रेप केस के आधार पर सुनील को ही कातिल मान लेगी, लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्यों और कड़ाई से हुई पूछताछ ने मां-बेटे की साजिश को बेनकाब कर दिया।

अपनी ही सरकार पर भाजपा विधायक का वार! योगी के मंत्री के कट्टर दुश्मन बने बृजभूषण राजपूत

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। बृजभूषण राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में योजना की प्रगति का निरीक्षण करते हुए कई गांवों में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन गांवों को 'पूर्ण संतृप्त' बताया गया है, वहां अब भी लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है।

चरखारी क्षेत्र के विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई जगह अधूरे काम दिखाई दिए। ग्रामीणों के अनुसार कई घरों के बाहर पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन नलों में टोंटियां नहीं लगी हैं और कई स्थानों पर सड़कें खुदाई के बाद ठीक नहीं की गई हैं। कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि अभी तक नियमित रूप से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।

निरीक्षण के दौरान विधायक ने ग्रामीणों से बातचीत भी की। कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें अब भी दूर से पानी लाकर घर का काम चलाना पड़ रहा है। इस दौरान विधायक ने गांव में उपलब्ध पानी का स्वाद लेकर भी स्थिति की जानकारी ली।

विधायक ने कहा कि यदि कहीं भी कार्यों में लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार ठेकेदारों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग भी उठाई है। इससे पहले भी विधायक जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में योजना का लाभ लोगों तक पूरी तरह पहुंचे, इसके लिए लगातार निगरानी और सुधार की जरूरत है। जल जीवन मिशन को लेकर उठे इन सवालों के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि निरीक्षण के बाद उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा।

शादी समारोह में पूर्व प्रधान पति की गोली मारकर हत्या, रंजिश में हत्या की आशंका

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में बागपत के दोघट कस्बे में एक विवाह समारोह में शामिल होने आये शामली जनपद के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में कारर्वाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में लिया है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया है।

मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कारर्वाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि करीब डेढ़ बजे पुलिस को सूचना मिली कि कस्बा दोघट में बारात में आए पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही दोघट थाना पुलिस तथा अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात्रि को शामली जनपद के बहावड़ी गांव निवासी विक्की उफर् विवेक (42)अपनी पत्नी और पूर्व प्रधान बबली के साथ बागपत के कस्बा दोघट में एक विवाह समारोह में बाराती के रूप में शामिल होने आये थे।

बताया गया कि जैसे ही वह फार्म हॉउस की पाकिर्ंग में पहुंचे तो उसी के गांव के ही दो लोगों ने गांव की पुरानी रंजिश को लेकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फार्म हॉउस में अचानक गोली चलने से वहां अफरातफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। फार्म हाउस के मालिक सुनील पंवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर दोघट पुलिस मौके पर पहुंची। वहां मौजूद लोगों ने गोली मारकर भाग रहे आरोपियों में से एक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बागपत पोस्टमाटर्म के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक की पत्नी बबली ने चार लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रहीं है।

यूपी में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत? योगी सरकार का बड़ा एक्शन कालाबाजारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपभोक्ताओं की रसोई गैस एजेंसियों के बाहर उमड़ती भीड़ के बीच राज्य सरकार ने पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस की आपूर्ति बाधित होने संबंधी अफवाहों और संभावित कालाबाजारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरे राज्य में कड़ी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग की टीम ने तेल और रसोई गैस की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए नोएडा से गोरखपुर तक जगह-जगह छापे मारे। अधिकारियों ने कहा कि मजिस्ट्रेट और प्रवर्तन दल गौतम बुद्ध नगर समेत विभिन्न जिलों में पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर सघन निरीक्षण कर रही है ताकि इन चीजों की कालाबाजारी न हो सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई हिस्सों से रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए बेचैन घरेलू उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गईं।

कुछ लोगों ने कहा कि वे सिलेंडर पाने के लिए कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। यहां कैसरबाग समेत शहर के कुछ स्थानों पर कुछ गैस एजेंसियों के बाहर रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और हालात पर नजर रखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई- को बताया, 'घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उपभोक्ताओं की सुविधा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अगर कोई व्यक्ति तेल या गैस की कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी।

भाजपा की अदूरदर्शिता ने बुझाया 'राम रसोई' का चूल्हा- अयोध्या में गैस सिलेंडर की किल्लत पर बोली कांग्रेस

अयोध्या। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के अध्योध्या में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से कई इलाकों में किल्लत बढ़ गई है। स्थिति यह है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग गैस एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं और लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। अयोध्या में गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने के कारण अमावा मंदिर स्थित राम रसोई में भोजन वितरण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह राम रसोई राम मंदिर की दीवार से सटी हुई है, जहां श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जाता था।

इसे लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावार हो गई है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खाड़ी के युद्ध की आंच अब अयोध्या की 'राम रसोई' तक आ पहुंची है, जहाँ सिलेंडर की किल्लत ने भक्तों के निवाले पर ताला लगा दिया है। हनुमानगढ़ी के प्रसाद पर मंडराता संकट भाजपा सरकार के उस खोखले 'मैनेजमेंट' की पोल खोल रहा है, जो आपदा आने से पहले ही घुटने टेक चुका है।

जो सरकार भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई, आज उसी के राज में राम रसोई का चूल्हा बुझना बेहद शर्मनाक है। क्या जनता ने इसीलिए वोट दिया था कि उन्हें अपनी आस्था और बुनियादी जरूरतों के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़े? भाजपा की ये अदूरदर्शिता आज हर श्रद्धालु और नागरिक के लिए भारी पड़ रही है।

मंदिर प्रबंधन के अनुसार रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते भोजन बनाने में कठिनाई आ रही है। इसी कारण फिलहाल भोजन वितरण को अस्थायी तौर पर रोकने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य होते ही राम रसोई में भोजन वितरण की सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, महर्षि महेश योगी आश्रम में संगीत ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से विश्व हुआ एकजुट

प्रयागराज/ऋषिकेश। अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के तीसरे दिन परम पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी और डा साध्वी भगवती सरस्वती जी के पावन सान्निध्य में महर्षि महेश योगी आश्रम की पवित्र भूमि पर एक विशेष ध्यान साधना का आयोजन किया। इस पवित्र स्थल पर योग महोत्सव में विश्वभर से आए साधक और प्रतिभागी एकत्र हुए और सामूहिक ध्यान तथा मंत्रोच्चार के माध्यम से आंतरिक शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया। डा साध्वी भगवती सरस्वती जी ने गाइडेड मेडिटेशन कराया।

विश्व शांति और सामंजस्य के लिए विशेष प्रार्थना की। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरित संवर्द्धन हेतु रूद्राक्ष के पौधों का रोपण करते हुये प्रकृति के साथ सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने का पूज्य स्वामी जी ने संदेश दिया और कहा कि यह वही दिव्य स्थल है जहाँ कभी बीटल्स ने ध्यान साधना की थी।

प्रसिद्ध कीर्तनगायक राधिका दास के कीर्तन की मधुर आवाज ने हृदय को छू लिया। प्रसिद्ध ड्रम वादक शिवमणि जी की ताल के ब्रह्मनाद ने पूरे वातावरण को प्रफुल्लित कर दिया, और रूना रिजवी शिवमणि की सुफियाना आवाज ने इस समग्र अनुभव को दिव्य बना दिया। महर्षि महेश योगी आश्रम की पवित्रता और इस संगीत-साधना के संगम ने सभी साधकों के हृदयों को गहन आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद भर दिया।

पूज्य स्वामीजी के श्रीमुख से गूँजें मंत्रों और हर शब्द ने साधकों के हृदय में दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। हर क्षण चेतना को जागृत करने वाला था, हर मंत्र सम्पूर्ण मानवता हो जोड़ने वाला और विश्व के कल्याण के लिए था।

स्वामीजी के नेतृत्व में हुआ यह मंत्रोच्चारण विश्व को जोड़ने, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जीवित रखने, और शांति एवं करुणा की चेतना को प्रसारित करने का दिव्य प्रयास है।

परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के प्रेरणास्रोत पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी ने कहा कि योग, शक्ति है, भक्ति है, संगीत है और शांति भी है। योग दिलों को जोड़ता है, देशों को जोड़ता है, प्रकृति और संस्कृति को जोड़ता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिव्य सेतु है।

उन्होंने वैश्विक योगी समुदाय का आह्वान करते हुये कहा कि योग की इस शक्ति से हम विश्व शांति की दिशा में कदम बढ़ाएँ। आइए भारत की दिव्य योग परंपरा और उत्तराखण्ड की पावन कंदराओं से निकलने वाली ध्यान-साधना की विधाओं को आत्मसात करते हेतु योग से जुड़ें, इसे जियें और जीवन को एक नई दिशा दें।

इस पवित्र आयोजन में डॉ. साध्वी भगवती सरस्वती जी ने गाइडेड मेडिटेशन कराते हुए प्रतिभागियों को अपने भीतर की ऊर्जा और शांति से जुड़ने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, भारत की सनातन आध्यात्मिक विरासत का जीवंत उत्सव है। जो हमें स्वयं से जोड़ता है, समाज से जोड़ता है और सम्पूर्ण मानवता को एकजुट करता है। वह भी ऐसे समय में जब विश्व बढ़ते संघर्ष और विभाजन का सामना कर रहा है, एकता और सामूहिक प्रार्थना के ये क्षण शांति, करुणा और मानवीय जुड़ाव की तत्काल आवश्यकता का शक्तिशाली स्मरण कराते हैं। यह महोत्सव एक ऐसा पवित्र मंच प्रदान करता है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, आस्थाओं और पृष्ठभूमियों के लोग सामंजस्य के साथ एकत्र होते हैं।

ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं के पश्चात, सभी प्रतिभागियों और योग जिज्ञासुओं ने माँ गंगा में पवित्र स्नान किया। मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर प्रतिभागियों ने अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया, और भक्ति, ध्यान एवं प्रार्थना के माध्यम से आत्मा को नव जीवन का अनुभव कराया।

तीसरे दिन की प्रभात बेला में जब हिमालय के आकाश में सूर्योदय की स्वर्णिम आभा फैल रही थी, तब प्रतिभागी शरीर को ऊर्जावान और मन को शांत करने वाली विशेष प्रातःकालीन साधनाओं के लिए एकत्र हुए। दिन की शुरुआत योगाचार्य दुर्गेश अमोली द्वारा संचालित हठ योग सत्र से हुई, जिसने पारंपरिक योगाभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों को स्थिरता और संतुलन प्रदान किया। योगाचार्य दासा दास ने 'एम्पावर एंड एनर्जाइज कुंडलिनी अवेकनिंग' सत्र का संचालन किया, जिसमें आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने और चेतना को सक्रिय करने की शक्तिशाली तकनीकों का अभ्यास कराया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग, माइंडफुलनेस और वेलनेस विशेषज्ञ डॉ. ईडन गोल्डमैन ने 'चिकित्सा विन्यास थेरेप्यूटिक फ्लो मास्टर क्लास' का संचालन किया, जिसमें योग थेरेपी के सिद्धांतों को सजग गतियों के साथ जोड़कर उपचार और शारीरिक सुदृढ़ता को बढ़ावा दिया गया।

श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान के पूर्वाध्यक्ष ने अपनी समस्त सम्पत्ति को बेचकर भी गोसेवा संतक्षण किया

सरकार को कोसने में लगे मठाधीश धर्माचार्य : अरविंद स्वामी

प्रयागराज। श्री स्वामी डूंग जी महाराज संस्थान (भूरा मठ) के पीठासीन अध्यक्ष विद्यामार्तण्ड अरविंद स्वामी जोशी ने कहा कि वर्तमान में कई धनाढ्य धर्माचार्य गो हत्या पर योगी-मोदी सरकार को गालियां दे रहे हैं। वह यात्रायें निकाल रहे हैं, लेकिन खुद के जीवन दर्शन में देखने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा पहले तो ऐसे भी संत हुआ करते थे, जो अपनी सारी संपत्ति बेचकर गोसेवा करते थे। श्री स्वामी हरीश्वरानन्द तीर्थ जी महाराज उर्फ हुकुमानन्द का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति को बेचकर के दो लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण किया। दण्डी सन्यासी समाज के वो महान सन्त थे। उनका सम्पूर्ण जीवन गो सेवा में लगा रहा।उन्होंने काशी, चित्रकूट, हरिद्वार, बृजघाट, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग तथा कोलकाता जैसे प्रमुख नगरों में स्थित विशाल भवनों का विक्रय करके भी गो वंश की रक्षा में सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें धर्मसम्राट श्री स्वामी करपात्री जी समेत 80 के दशक के सभी महान सन्तों की सेवा तथा अपने संस्थान में आकर निवास करते देखा गया। सवाल किया कि क्या आज अरबों की सम्पत्ति के साम्राज्य पर बैठे कुछ एक बड़े धर्माचार्यों का कर्तव्य नहीं बनता कि वह योगी-मोदी को गालियां अथवा कोसने को त्याग कर अपने अपार धन वैभव का त्याग करके अपने चांदी-सोने के सिंहासनों से मुक्त होकर स्वावलम्ब रूप से समाज को गो वध से मुक्त करें? क्या उन्हें समाज के धन पर स्वयं की सुख सुविधा और मोटी दक्षिणा इसलिए दी गयी है कि केवल ज्ञान बांटिये ? यह वर्तमान समय में विचार का प्रश्न है और हर धर्मज्ञ व्यक्ति को अवश्य उन महात्माओं से पूछना चाहिए जो योगी और मोदी को भर-भर पेट गालियां बक रहे हैं।

प्राथमिक विद्यालय रामपुर दुआरी में वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न

थरवई (प्रयागराज)। विकासखंड सोरांव के प्राथमिक विद्यालय रामपुर दुआरी में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम पूरे उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक राजेश त्रिपाठी पाण्डेय द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा पांच के छात्र-छात्राओं को कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हुआ। प्रधानाध्यापक डॉ राजेश त्रिपाठी पाण्डेय ने कहा की ऐसे आयोजनों से बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी प्रतिभाओं को मंच मिलता हैकार्यक्रम में प्रमुख रूप से ए आर पी शिक्षक अखिलेश शुक्ला, अभिनव उपाध्याय, दयानंद मिश्र, रमाकांत द्विवेदी, इदू मिश्रा, अमरेश राय, संतलाल चौरसिया दिलीप तिवारी रीता शर्मा सहित कई शिक्षक अभिभावक व क्षेत्रीय गढ़ मान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

लंबी बीमारी के बाद पत्रकार मोहम्मद कयूम के बड़े भाई का निधन

ताजुद्दीनपुर गांव में शोक की लहर, लोगों ने पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

थरवई (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव निवासी हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार मोहम्मद कयूम के बड़े भाई मोहम्मद गुलशेर अली (66) का बुधवार दोपहर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मद गुलशेर अली, पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद शमीउल्ला, काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। बुधवार दोपहर अचानक उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया।

निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, शुभचिंतक एवं ग्रामीण उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने लगे। बताया जाता है कि वह चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके निधन से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरा परिवार गहरे गम में डूबा हुआ है।

युवती को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज

थरवई (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के मनसैता गांव निवासी पंकज कुमार यादव की तहरीर पर पुलिस ने शिवम यादव पुत्र राजेश यादव व एक अज्ञात के खिलाफ उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना 7 मार्च की है। पुलिस युवती की तलाश में जुटी है।

संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत

थरवई (प्रयागराज)। थाना क्षेत्र के हेतापट्टी बाजार निवासी रामसेवक पटवा (44) पुत्र स्व. भाई लाल की मंगलवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

महानगरपालिका को करीब 1 लाख का नुकसान.

भिवंडी में पानी माफिया का खेल ! पाइपलाइन में छेद कर 4 साल से हो रही थी पानी की चोरी.

सर्विस सेंटर चलाने वाला आरोपी केस दर्ज होते ही घेरे में

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में पानी चोरी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका की कार्रवाई में खुलासा हुआ कि एक व्यक्ति पिछले चार साल से मुख्य पाइपलाइन में छेद कर अवैध तरीके से पानी की सप्लाई लेकर अपना सर्विस सेंटर चला रहा था। मामले का पर्दाफाश होते ही महानगरपालिका ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। महानगरपालिका द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 9 मार्च 2026 को सुबह करीब 11:50 बजे निजामपुरा स्थित ममता हॉस्पिटल के सामने शानदार मार्केट, नाशिक रोड इलाके में पानी पुरवठा विभाग की टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान टीम को मुख्य जल पाइपलाइन में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि अबू शहाद सिद्दीकी नामक व्यक्ति ने बिना किसी अनुमति के पाइपलाइन में छेद कर आधा इंच व्यास का अवैध नल कनेक्शन जोड़ रखा था और इसी के जरिए अपने सर्विस सेंटर के लिए पानी की व्यवस्था कर रहा था। अधिकारियों के मुताबिक इस अवैध कनेक्शन के कारण महानगरपालिका को लगभग चार वर्षों में 99,400 रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें प्रति कनेक्शन 12 हजार रुपये के हिसाब से चार साल का 48 हजार रुपये, खड्डा पावती शुल्क 1,400 रुपये और अन्य शुल्क शामिल हैं। इस मामले में 10 मार्च 2026 को शांतीनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(4), 326(क) और 303(2) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई महानगरपालिका आयुक्त अनमोल सागर और अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाने के निर्देश पर की गई। कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर के मार्गदर्शन में उप अभियंता सरफराज अंसारी के नेतृत्व में पथक प्रमुख विराज भोईर और सहायक पथक प्रमुख नफीस मोमिन की टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई अंजाम दी।महानगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना अनुमति जल कनेक्शन लेने से बचें। यदि कहीं भी अवैध पानी उपयोग की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

भिवंडी मनपा में लाइसेंस दरसूची को लेकर संगठनों के साथ बैठक

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के विज्ञापन एवं परवाना (लाइसेंस) विभाग की ओर से लाइसेंस पंजीकरण, नवीनीकरण और लाइसेंस दरसूची के संबंध में विभिन्न संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई.यह बैठक मनपा आयुक्त अनमोल सागर और अतिरिक्त आयुक्त नयना ससाणे के निर्देशानुसार उपआयुक्त (परवाना) बालकृष्ण क्षीरसागर की अध्यक्षता में उनके दफ्तर में हुई। बैठक में लाइसेंस पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस दरसूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि आसपास की महानगरपालिकाओं की लाइसेंस दरसूची का तुलनात्मक अध्ययन कर उचित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उसे आगामी महासभा में पेश किया जाएगा। इसके बाद सर्वसम्मति से उपयुक्त दरसूची पर निर्णय लिया जाएगा। उपआयुक्त बालकृष्ण क्षीरसागर ने कहा कि इस प्रक्रिया से लंबे समय से लंबित लाइसेंस विभाग की वसूली और नवीनीकरण को गति मिलेगी। इससे महानगरपालिका की आय बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। बैठक में सहायक आयुक्त (परवाना) नितीन पाटील, विज्ञापन परवाना विभाग प्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी, मेडिकल एसोसिएशन के अशोक डोडी तथा बार एंड परमिट रूम एसोसिएशन के प्रज्वल शेट्टी और रामकृष्ण शेट्टी मौजूद थे।

नाबालिग से छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की व उसकी मां को पीटा तीन पर केस दर्ज, गिरफ्तार

भिवंडी। शहर के घुंघटनगर इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की और उसकी मां के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार 38 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। घटना 4 मार्च 2026 की शाम करीब 5:30 बजे घुंघट स्थित उनके घर के सामने हुई। शिकायत के मुताबिक महिला की 16 वर्षीय बेटी घर के सामने खड़ी थी। उसी दौरान कमलेश नामक युवक ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की। जब लड़की की मां ने इसका विरोध किया तो आरोपी कमलेश के साथ पवन और जोगिंदर भी वहां पहुंच गए।तीनों आरोपियों ने मिलकर महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने हाथ, मुक्कों और लातों से दोनों को पीटा, जिससे उन्हें चोटें आईं। घटना के बाद पीड़िता ने शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 115(2) और 3(5) सहित पोक्सो कलम 8,12 के तहत मामला दर्ज किया है।पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं और मामले की आगे की जांच की जा रही है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती से दुष्कर्म, मामला दर्ज

भिवंडी। शहर के नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार कामतघर इलाके की रहने वाली युवती की पहचान उसी क्षेत्र में रहने वाले विकास संजय गौतम (21) से हुई थी। आरोप है कि युवक ने युवती से शादी करने का वादा किया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के मुताबिक 28 जुलाई 2025 से 8 मार्च 2026 के बीच आरोपी ने कई बार युवती के साथ जबरन संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई, जिसके बाद मामला सामने आया। घटना के बाद पीड़िता ने नारपोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 69,71 सहित पोक्सो की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश लक्ष्मी रंगनाथ राव वडणे कर रहे हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और आगे की जांच जारी है।

'बंजारा' को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उच्च स्तरीय अध्ययन समिति रद्द करें!

ट्रायबल फोरम की मांगः राज्यपाल, मुख्यमंत्री को ज्ञापन.

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सुनील झलके, कार्याध्यक्ष, ट्रायबल फोरम कोकण विभाग

भिवंडी। बंजारा वर्ग के उपवर्ग सहित सदर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जांच करने के लिए अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 27 फेब्रुवारी 2026 को समिति स्थापित की गई है। इस समिति को रद्द करें। ऐसी मांग महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री से ट्रायबल फोरम कोकण विभाग के विभागीय कार्याध्यक्ष सुनील झळके ने ज्ञापन के माध्यम से की है। राज्य में 'बंजारा' समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इस मांग के लिए पिछले छह महीनों से राज्य के आदिवासी समाज ने हजारों, लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर मोर्चे निकाले। इस मोर्चे से आदिवासी समाज ने प्रखर विरोध किया। यह सर्वविदित है, इसके बावजूद आदिवासी समाज के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2025 को सह्याद्री अतिथि ग्रह पर बैठक हुई और 'बंजारा' वर्ग के उपवर्ग सहित सदर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने की जिम्मेदारी आदिवासी विकास विभाग को सौंपी गई। आदिवासी विकास विभाग ने अब समिति का गठन किया है। यह समिति तीन महीनों में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे आदिवासी समाज में भय का वातावरण निर्माण हुआ है। केंद्र ने खारिज किया, राज्य ने भी प्रस्ताव वापस लिया.....

राज्य सरकार ने 'बंजारा' जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए 12 जून 1979 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। 'बंजारा' समाज आदिवासियों के निकष पूर्ण नहीं करता है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने भी अपना प्रस्ताव 6 नवंबर 1981 को पूर्ण विचारण के बाद वापस ले लिया था। फिर भी 44 वर्षों के बाद फिर से बंजारा समावेश के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति स्थापित की है।

बंजारा आदिवासी नहीं है.....

केंद्र सरकार ने 6 फेब्रुवारी 1981 को एक जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्राचीन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृति, स्वभाव में बुजरेपणा, पिछड़ापन ये पांच निकष निर्धारित किए थे। ये निकष 'बंजारा' पूर्ण नहीं करता है। फिर भी जानबूझकर आदिवासी समाज में घुसाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। बंजारा आदिवासी नहीं हैं। 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्र के संबंध में 6 सितंबर 1950 को राष्ट्रपति के पहले आदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र राज्य के लिए संसद ने समय-समय पर संशोधन किए गए अनुसूचित जनजाति की सूचियां सूचीबद्ध की गई हैं। इसमें 'बंजारा' ऐसी कोई नोंद नहीं है। हमारे ऊपर जानबूझकर संघर्ष लाया जा रहा है।

मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) गुरूवार और शुक्रवार तक डिस्क डी-फ्रैग्मेंटेशन कार्य के लिए बंद रहेगी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई पीआरएस दिनांक 12.03.2026 को 23.45 बजे से दिनांक 13.03.2026 को 03.15 बजे तक डिस्क डी-फ्रैग्मेंटेशन कार्य के लिए बंद रहेगी।

रेलवे सेवा बंद होने के कारण, उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगीङ

यात्री आरक्षण प्रणाली,
कोचिंग रिफंड,
चार्टिंग गतिविधियां,
ट्रेन फायरिंग,
आईवीआरएस,
करेंट आरक्षण,
चार्ट डिस्प्ले,
टच स्क्रीन,
रिफंड काउंटर और
कोचिंग रिफंड टर्मिनल

हालांकि, मौजूदा रिफंड नियमों के अनुसार टीडीआर जारी किया जाएगा। उपरोक्त अवधि के दौरान मुंबई पीआरएस ट्रेनों के लिए इंटरनेट बुकिंग उपलब्ध नहीं होगी।

यात्रियों/रेल उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण रखरखाव कार्य के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

टोरेंट पावर की ओर से भिवंडी में दावत-ए-इफ्तार का आयोजन

सामुदायिक एकता का संदेश

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। पवित्र रमजान माह के अवसर पर टोरेंट पावर द्वारा भिवंडी में भव्य दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर में सामाजिक सौहार्द, एकजुटता और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बतादें कि मंगलवार 10 मार्च 2026 को अशोक नगर स्थित पाटीदार हॉल में आयोजित इस इफ्तार कार्यक्रम में शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी, महानगरपालिका के अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, मीडिया से जुड़े लोग तथा क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर टोरेंट पावर के वरिष्ठ अधिकारियों जीवन क्लर्क (उपाध्यक्ष), जय पांड्या, सुधीर देशमुख और चेतन बदियानी सहित कंपनी की टीम ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में धर्मगुरु सय्यद मुफ्ती मोहम्मद हुजैफा कासमी ने उपस्थित लोगों को रमजान और इफ्तार के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना आपसी भाईचारे, सहयोग और मानवता का संदेश देता है तथा ऐसे आयोजन समाज में एकता को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने टोरेंट पावर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम शहर के नागरिकों के बीच सहयोग, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। टोरेंट पावर के जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदियानी ने बताया कि कंपनी ने अपने लोगो में भी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से कंपनी और समाज के बीच संबंध और अधिक मजबूत होते हैं।

यूपी में एलपीजी सिलेण्डर पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सीएम योगी का अल्टीमेटम- होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चेतावनी दी कि उत्तर प्रदेश में तेल या गैस की कमी के बारे में अफवाहें फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य भर के सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्रमुखों को सख्त निर्देश जारी करते हुए उन्हें सतर्क रहने और गलत सूचनाओं के कारण जनता में दहशत न फैलने देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देते हुए कहा कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अफवाहें फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी तेज कर दी गई है। सभी जिलों में पुलिस टीमों को पेट्रोल पंपों के आसपास कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि जमाखोरी और अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। साथ ही, जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को गैस एजेंसियों और दुकानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को एलपीजी सिलेंडरों का अवैध भंडारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। राज्य सरकार की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। इस संकट ने भारत की लगभग 30 प्रतिशत गैस आपूर्ति को प्रभावित किया है, जिसके चलते केंद्र सरकार को आपातकालीन उपाय करने पड़े हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया है कि उपलब्ध गैस को गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से आवश्यक उपयोगकर्ताओं की ओर मोड़ा जाए।

भारत वर्तमान में अपनी दैनिक प्राकृतिक गैस की मांग (191 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन) का लगभग आधा हिस्सा आयात से पूरा करता है। हालांकि, होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकरों की आवाजाही बाधित होने के कारण मध्य पूर्व से लगभग 60 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है।

3.95 करोड़ रुपये के इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, बीजापुर और दंतेवाड़ा के 67 नक्सली भी शामिल

बस्तर । देश में 31 मार्च तक नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है। माओवादियों में भी आत्मसमर्पण करने की होड मच गई है। छत्तीसगढ़ में 3.95 करोड़ रुपये के इनामी 108 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें बीजापुर और दंतेवाड़ा के 67 नक्सली भी शामिल हैं।

रैंक की बात करें तो बीजापुर में डीवीसीएम रैंक के तहत दो नक्सली, पीपीसीएम रैंक में 4, एसीएम में 9 और पीएम रैंक वाले 22 नक्सलियो ने सरेंडर किया है। कुल 37 नक्सलियों पर 106 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। नारायणपुर में डीवीसीएम रैंक के तहत एक नक्सली, सीवाईपीसीएम का एक, पीपीसीएम का एक और पीएम रैंक वाले दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 22 लाख रुपये का इनाम रखा गया था।

बस्तर में डीवीसीएम रैंक का 1, पीपीसीएम के पांच, एसीएम के तीन और पीएम रैंक वाले सात नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुल 16 नक्सलियों पर 99 लाख रुपये का इनाम है।

डेनवर की 'हवा' ने छीनी कार्डी बी की सांसें? शो के बाद ऑक्सीजन मास्क के साथ दिखीं रैपर, फैंस हुए हैरान

इंटरनेशनल रैप सेंसेशन कार्डी बी अपने बेबाक अंदाज और हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, हाल ही में डेनवर में हुए उनके एक कॉन्सर्ट के बाद सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सामने आए, जिन्होंने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया। वीडियो में कार्डी बी बैकस्टेज ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करती नजर आ रही थीं। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वायरल हुए इस वीडियो में देखा गया कि कार्डी बी को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन दी गई। जैसे ही यह क्लिप इंटरनेट पर फैली, फैंस के बीच उनकी सेहत को लेकर अटकलें तेज हो गईं।

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गए, जिससे फैंस में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि शो के दौरान आर्टिस्ट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। खुद इस स्थिति पर बात करते हुए, कार्डी बी ने इस पल को हल्के में लिया। बैकस्टेज फिल्माए गए एक वीडियो में, उन्होंने शहर की पतली हवा का मज़ाक उड़ाते हुए कहा, 'डेनवर की हवा, यह एक अलग तरह की म्यूचुअल फंड हवा है।'

मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम ऊंचाई से आने वाले लोगों को अक्सर ज़्यादा ऊंचाई वाले माहौल में एडजस्ट होने में समय लगता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से सांस लेने में तकलीफ, थकान, चक्कर आना और सांस तेज़ होने जैसे लक्षण हो सकते हैं - ये असर गाने और डांस जैसी शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत वाली एक्टिविटीज़ के दौरान ज़्यादा दिखते हैं।

परफॉर्मर्स और एथलीटों के लिए, ऐसी स्थितियों में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना कोई अजीब बात नहीं है। कई टूरिंग आर्टिस्ट ऊंचाई में बदलाव के साथ अपने शरीर को संभालने में मदद करने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाते हैं, खासकर हाई-एनर्जी शो के दौरान। ज़्यादातर मामलों में, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत टेम्परेरी होती है जब तक कि शरीर मौसम के हिसाब से ढल न जाए।

यह पल ऐसे समय में भी आया जब कार्डी बी स्टेफ़न डिग्स से अलग होने की खबर के बाद पर्सनल मुश्किलों से जूझ रही थीं। हालांकि ऑक्सीजन मास्क वाली घटना ज़्यादातर डेनवर की ऊंचाई से जुड़ी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि क्या हाल की हेडलाइंस के इमोशनल तनाव ने पर्दे के पीछे के दबाव को और बढ़ा दिया होगा।

बैकस्टेज के उस छोटे से पल के बावजूद, रैपर ने अपनी परफॉर्मेंस सफलतापूर्वक पूरी की और अच्छे मूड में दिखीं। कार्डी बी ने बाद में इस अनुभव के बारे में मज़ाक भी किया।

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश : पहले वनडे में 114 रन पर ढेर हुआ पाकिस्तान, बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 114 रन पर ऑलआउट हो गई। यह बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है।

यह मुकाबला ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का सबसे कम वनडे स्कोर 161 रन था। यह स्कोर 1999 वर्ल्ड कप में बना था, जब बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन अब 2026 में पाकिस्तान की टीम उस रिकॉर्ड से भी नीचे गिर गई और सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई।

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। नई ओपनिंग जोड़ी माज़ सादाकत और साहिबजादा फरहान ने तेज शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने फरहान को आउट करके पाकिस्तान की पारी को बड़ा झटका दिया।

नाहिद राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। उन्होंने पहले साहिबजादा फरहान (27) को आउट किया और इसके बाद डेब्यू कर रहे शमील हुसैन (4) को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद राणा ने माज़ सादाकत (18) को भी आउट कर दिया, जिससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्होंने आगे मोहम्मद रिजवान (10) और सलमान अली आगा (5) को भी आउट कर अपना पांच विकेट हॉल पूरा किया।

तेज गेंदबाजों के साथ-साथ बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। मिराज ने पाकिस्तान के मध्य और निचले क्रम को झटके देते हुए तीन अहम विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना सके और लगातार विकेट गिरते रहे।

पाकिस्तान की टीम एक समय 70 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी। अब्दुल समद बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि हुसैन तलत (4) भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश की, लेकिन वह भी 4 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।

नेमार ने वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर आशंका के बीच निकाला गुस्सा, कहा- करीबी लोगों ने किया निराश

रियो डी जेनेरियो। नेमार ने मिरासोल के साथ सैंटोस के अवे मैच के लिए टीम से बाहर किए जाने पर गुस्सा जताया, जिससे इस साल के फीफा वर्ल्ड कप से पहले उनकी फिटनेस पर नए शक पैदा हो गए हैं। 34 साल के इस खिलाड़ी के मंगलवार रात के सीरी ए मैच में चोट के कारण बाहर रहने के बाद वापसी की उम्मीद थी।

ब्राजीलियन फुटबॉल कन्फेडरेशन ने पहले कहा था कि नेशनल टीम के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी इस महीने के आखिर में फ्रांस और क्रोएशिया के खिलाफ वर्ल्ड कप वार्म-अप मैचों के लिए अपनी टीम का नाम बताने से पहले नेमार का हालचाल जानने के लिए मैच में आएंगे। लेकिन इस फैसले से यह चिंता बढ़ गई कि क्या बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन के पूर्व स्टार जून और जुलाई में होने वाले फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार होंगे।

नेमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, 'क्योंकि बहुत से लोग मेरे साथ जो हो रहा है, उसके बारे में थ्योरी बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं चोटिल होकर खेलता हूं, जैसा कि उन्होंने पिछले साल कहा था, तो मैं गलत हूं। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं, तो मैं गलत हूं। अगर मैं खुद को रोकता हूं, तो मैं गलत हूँ। अगर मैं दर्द के साथ खेलता हूं या ऐसी किसी चीज के साथ जो इसे और खराब कर सकती है, तो मैं गलत हूं। यह मुश्किल है, है ना? इसे सही करना बहुत मुश्किल है, यार। बहुत मुश्किल, सबको खुश करना बहुत मुश्किल है।' नेमार, जो 128 गेम में 79 गोल के साथ ब्राजील के ऑल-टाइम लीडिंग स्कोरर हैं, ने कहा कि उन्हें अपने करीबी लोगों ने निराश किया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, 'मुझे सबसे ज्यादा हैरानी उन लोगों से होती है, असल में, यह मुझे हैरान नहीं करता, जो हर दिन मेरे साथ रहते हैं और कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं, यह-वह कहते हैं जैसे कि यह बिल्कुल सच हो, जैसे कि वे ही सब कुछ जानते हों। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, हे भगवान। आप सभी को झेलने के लिए मुझे बहुत सब्र रखना होगा।'

दिसंबर में अपने बाएं घुटने की आर्थोस्कोपिक सर्जरी के बाद नेमार इस साल सैंटोस के लिए सिर्फ तीन मैच खेले हैं। अक्टूबर 2023 में उरुग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट फटने के बाद से वह ब्राजील के लिए नहीं खेले हैं, इस चोट की वजह से वह एक साल से ज़्यादा समय तक बाहर रहे। एंसेलोटी ने कहा है कि वह अपनी वर्ल्ड कप टीम चुनते समय सिर्फ उन खिलाड़ियों पर विचार करेंगे जो अपने क्लब के लिए रेगुलर खेल रहे हैं।

इंडियन वेल्स : ओसाका को हराकर क्वार्टरफाइनल में पहुंची सबालेंका

कैलिफोर्निया। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने नाओमी ओसाका को हराकर इंडियन वेल्स के क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है। 27 साल की बेलारुस की सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान की ओसाका को 80 मिनट चले मुकाबले में 6-2, 6-4 से हरा कर टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश किया।

जुलाई 2023 में बेटी शाई के जन्म के बाद 14 महीनों के बाद वापसी कर रही ओसाका ने मैच की शुरुआत एक कॉन्फिडेंट ओपनिंग सर्विस गेम से की। हालांकि, सबालेंका ने जल्द ही अपनी रिदम पकड़ ली और 28 साल की जापानी खिलाड़ी की सर्विस तोड़कर 2-1 की बढ़त बना ली।

बेलारूसी खिलाड़ी ने कई दमदार बैकहैंड मारकर अपनी पकड़ मजबूत की और 5-2 की बढ़त बना ली, फिर एक ऐस के साथ आराम से सेट जीत लिया। ओसाका और सबालेंका दोनों ने दूसरे सेट की शुरुआत में सर्विस बनाए रखी, फिर सबालेंका ने 4-2 से कंट्रोल हासिल किया और फिर एक अहम ब्रेक के साथ मैच जीत लिया।

मैच के बाद सबालेंका ने कहा, 'यह पागलपन है, इतने सालों में हमने सिर्फ एक बार खेला। मुझे पूरा यकीन है कि हम और भी कई मैच खेलेंगे। वह शानदार टेनिस खेलकर वापस आ रही है। मैं नतीसे से बहुत खुश हूं। पिछली बार से बहुत बेहतर। मुझे खुशी है कि मैंने आज उन पर इतना प्रेशर डाला, कि मैं कोटर् में वैरायटी लेकर आई। मेरी सर्विस ने अच्छा काम किया। रिटर्न पर मैंने सच में बहुत अच्छा टेनिस खेला। मैं अपने परफॉर्मेंस से पक्का खुश हूं।' दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टालिया गिब्सन ने इटली की दुनिया की नंबर सात जैस्मीन पाओलिनी को 7-5, 2-6, 6-1 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की, यह उनका टॉप-10 खिलाड़ी के खिलाफ पहला मैच था। 21 साल की गिब्सन, जो दुनिया में 112वें नंबर पर हैं और अपना पहला डब्ल्यूटीए 1000 मेन ड्रॉ खेल रही हैं, 11 साल में टूर्नामेंट के क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर भी बनीं।

ईरान संकट से बढ़ सकती है तेल कंपनियों की मुश्किलें, कमाई और कैश फ्लो पर दबाव की चेतावनी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अब भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर भी दिखने लगा है। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी सरकारी तेल विपणन कंपनियों की आय में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि अप्रैल 2022 से पेट्रोल-डीजल के रिटेल दाम लगभग स्थिर हैं, जबकि वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने पर इन कंपनियों को बढ़ी हुई लागत का बड़ा हिस्सा खुद ही उठाना पड़ता है, जिससे उनका विपणन मार्जिन और नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के करीब 90 प्रतिशत पेट्रोल पंप वाले तीन कंपनियां के नियंत्रण में हैं, इसलिए ईंधन कीमतों को स्थिर रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ाए पर ज्यादा रहती है। हाल ही में वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, हालांकि बाद में यह गिरकर 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरी ओर फिच रेटिंग्स ने कहा है कि अगर ईरान से जुड़ तनाव लंबा खंटा है और होर्मुज जलडमरूमध्य में विवादित प्रभावित होता है, तो भारतीय तेल विपणन कंपनियों के साथ-साथ गेल (इंडिया) लिमिटेड के नकदी प्रवाह पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि एजेंसी का कहना है कि सरकारी समर्थन के कारण इन कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग पर तत्काल कोई खतरा नहीं है।

एलपीजी की कमी पर सरकार का बड़ा अपडेट, घबराकर बुक न करने की अपील, ढाई दिन बाद मिलेगा सिलेंडर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। गैस की कमी की आशंकाओं के बीच सरकार ने कहा है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)के दो कार्गो भारत की ओर आ रहे हैं। 11 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह जानकारी दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने कहा कि बुकिंग के ढाई दिन बाद सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने जनता से अपील भी की है कि लोग घबराहट में सिलेंडर बुक करके जमा न करें। इसमें कहा गया कि एलपीजी की बढ़ी लागत का बोझ सरकार ने उठाया। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत में एलपीजी सस्ती है।

देश में एलपीजी की घबराहट में हो रही बुकिंग को लेकर भी सरकार ने सफाई दी है। सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी की सामान्य डिलीवरी साइकिल करीब ढाई दिन की ही बनी हुई है। इसलिए ग्राहकों को जल्दबाजी में सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच सरकार लगातार ऊर्जा सप्लाई की निगरानी कर रही है और जरूरी कदम उठा रही है। सरकारी अधिकारी के मुताबिक देश की रिफाइनरियां इस समय अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं। कुछ रिफाइनरियां अपनी निर्धारित क्षमता से भी ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत में गैस की कुल खपत करीब 189 एमएमएससीएमडी है। इसमें से 97.5 एमएमएससीएमडी गैस देश में ही उत्पादन होती है, जबकि बाकी गैस आयात की जाती है। फोर्स मेज्योर जैसी स्थितियों के कारण करीब 47.4 एमएमएससीएमडी गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में क्रूड ऑयल की सप्लाई फिलहाल सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि आज जितनी मात्रा में क्रूड सुरक्षित किया गया है, वह आम तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य से आने वाली सप्लाई से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अलग-अलग देशों से कई क्रूड कार्गो सुनिश्चित किए हैं। अभी भारत का करीब 75 प्रतिशत क्रूड आयात होर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों से आ रहा है, जबकि पहले यह हिस्सा करीब 55 प्रतिशत था।

मिडिल ईस्ट तनाव से संकट में पोल्ट्री उद्योग, 3.5 करोड़ अंडे रास्ते में फंसे, कीमतें धड़ाम

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। तमिलनाडु के नमक्कल, जिसे देश में 'एग सिटी' के नाम से जाना जाता है, के पोल्ट्री किसान इन दिनों भारी संकट का सामना कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अंडों का निर्यात प्रभावित हुआ है, जिससे इसकी कीमतें धड़ाम हो गईं। किसानों को बेहद कम कीमत पर अंडे बेचने पड़ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, खाड़ी देशों के लिए भेजे गए करीब 3.5 करोड़ अंडे बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। ये अंडे 28 फरवरी को लगभग 70 कंटेनरों में लोड होकर रवाना किए गए थे लेकिन लाल सागर और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते जहाज आगे नहीं बढ़ पाए।

प्रत्येक कंटेनर में करीब 5 लाख अंडे लोड थे। प्रति अंडा करीब 4.80 रुपए की कीमत के हिसाब से करीब 16-17 करोड़ रुपए का माल दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा कंटेनर किराया और ईंधन की लागत अलग से है।

नमक्कल भारत के कुल अंडा निर्यात का करीब 95 प्रतिशत संभालता है। यहां से बड़ी मात्रा में अंडे ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे खाड़ी देशों को भेजे जाते हैं। इस क्षेत्र में रोजाना लगभग 6 से 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है।

निर्यात प्रभावित होने के कारण जो अंडे विदेश भेजे जाने थे, वे अब घरेलू बाजार में ही आ रहे हैं। इससे बाजार में आपूर्ति अचानक बढ़ गई है और स्टॉक लगातार जमा हो रहा है। चूंकि अंडों की शैल्फ लाइफ सीमित होती है और तापमान बढ़ने पर वे जल्दी खराब हो सकते हैं, इसलिए किसान इन्हें कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं।

मधुबाला की बायोपिक में अनीत पड्डा की एंट्री? वायरल हो रही खबर के पीछे का असली सच

मुंबई। बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म 'सैयारा' (2025) से रातों-रात चर्चा में आईं अभिनेत्री अनीत पड्डा इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया और फिल्मी गलियारों में यह खबर तेजी से फैली कि अनीत पड्डा को भारतीय सिनेमा की 'वीनस' कही जाने वाली दिवंगत अभिनेत्री मधुबाला की बायोपिक के लिए चुन लिया गया है। लेकिन, क्या वाकई अनीत पड्डा पर्दे पर मधुबाला बनने जा रही हैं? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये खबरें तब आईं जब कियारा आडवाणी और त्रिप्ति डिमरी के नाम भी सामने आए। इस बीच, इंडस्ट्री के सूत्रों ने इन खबरों को झूठा और 'बेबुनियाद' बताया है।

पिछले कुछ दिनों से मशहूर स्क्रीन आइकन मधुबाला पर बायोपिक बनने की अटकलें ऑनलाइन चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया था कि एक्टर अनीत पड्डा आइकॉनिक स्टार का रोल करेंगी। हालांकि, इंडस्ट्री के सूत्रों ने अब इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है।

एक इंडस्ट्री सोर्स ने साफ किया है कि अनीत पड्डा को मधुबाला की बायोपिक से जोड़ने वाली खबरें गलत हैं। इंडस्ट्री सोर्स ने कहा, 'मधुबाला की बायोपिक में अनीत पड्डा को कास्ट किए जाने की जो खबरें चल रही हैं, उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।' मधुबाला पर बायोपिक बन रही है या नहीं, यह भी अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुआ है।

अक्टूबर 2025 में, ऐसी अफवाहें भी थीं कि अनीत पड्डा शक्ति शालिनी में कियारा आडवाणी की जगह ले सकती हैं। उस समय, मैडॉक फिल्म्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ इन अटकलों पर बात की और दावों को खारिज कर दिया।

स्टेटमेंट में लिखा था, 'हालांकि हम सच में अपने हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के एक्साइटमेंट को वैल्यू देते हैं, हम यह बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि शक्ति शालिनी और महा मुंज्या सहित आने वाले चैप्टर्स की कास्टिंग के बारे में कोई भी रिपोर्ट पूरी तरह से अंदाज़ा है।'

अनीत पड्डा के लिए आगे क्या है? अनीत पड्डा ने डायरेक्टर नित्या मेहरा की प्राइम वीडियो सीरीज़ बिग गर्ल्स डोंट क्राई (2024) से एक्टिंग में डेब्यू किया। बाद में उन्हें मोहित सूरी की डायरेक्ट की हुई थिएटर में रिलीज़ हुई सैयारा (2025) से ज़्यादा पहचान मिली। अनीत, अगली बार कोर्टरूम ड्रामा न्याय में नज़र आएंगी, जिसमें वह एक बार फिर नित्या मेहरा के साथ काम करेंगी। इस फ़िल्म में फातिमा सना शेख और अर्जुन माथुर भी हैं।

मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पर सरकार का बड़ा बयान, वित्त मंत्री ने लोकसभा में किया हैरान करने वाला खुलासा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सरकार ने साफ किया है कि उसने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगाए जाने वाले पेनल्टी चार्ज को माफ करने के लिए बैंकों को कोई सीधा निर्देश नहीं दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि कुछ सरकारी बैंकों ने ग्राहक-हित को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से इन चार्ज की समीक्षा की है और कई मामलों में इन्हें खत्म भी किया है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से कुल 8, 092.83 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में वसूले। हालांकि सरकार का कहना है कि यह राशि बैंकों की कुल आय का केवल करीब 0.23 प्रतिशत है और इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि बैंकिंग सेवाओं की लागत की भरपाई करना है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे खाते हैं जिनमें किसी तरह का मिनिमम बैलेंस जरूरी नहीं होता। इनमें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट और प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते शामिल हैं। इन खातों पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती और ऐसे लगभग 72 करोड़ खाते देश में मौजूद हैं।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, कई सरकारी बैंकों ने हाल के वर्षों में ग्राहकों के हित में सर्विस चार्ज में बदलाव किए हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2020 में सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाला पेनल्टी चार्ज खत्म कर दिया था। इसके अलावा 2025 में नौ अन्य सरकारी बैंकों ने भी ऐसे चार्ज पूरी तरह माफ कर दिए, जबकि कुछ बैंकों ने इन्हें कम किया है।

मध्य रेल
सोलापुर मण्डल
विद्युत कार्य

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि), मध्य रेल, सोलापुर, निम्नलिखित कार्य के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेल्वे की ई प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई निविदा आमंत्रित करते हैं। **निविदा क्रं :** सोला/जी.एस.यू/क.वि./नि/2025/01R1। **कार्य का नाम :** सोलापुर डिवीजन में दौंड-सोलापुर सेकशन के किमी 387/3-4 पर एलसी-40 और किमी 391/8-9 पर एलसी-42 के स्थान पर 2 लेन आरओबी के प्रस्तावित निर्माण के संबंध में विद्युत टीआरडी कार्य। (पुनर्निविदा) **अनुमानित लागत :** ₹ 62,47,420.20। **बयाना राशि :** ₹ 1,25,000/-। **कार्य पुरा करने की अवधि :** 12 माह। **निविदा प्रस्ताव की वैधता :** 60 दिन। **वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय :** दि. 06.04.2026 को 15.00 बजे। EXP-09

टिकट के लिए RailOne App डाउनलोड करे

पूर्वोत्तर रेलवे
निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/रिपेयर, वास्ते मुख्य कारखाना प्रबन्धक यांत्रिक कारखाना गोरखपुर द्वारा नीचे लिखे कार्य के लिए ऑनलाईन (ई–टेण्डरिंग) के माध्यम से एकल ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। **क्रम सं० (1) ई–निविदा सूचना सं० एवं निविदा कार्य का विवरण :** टेण्डर नं०–"57–जीकेपी– एमडब्लूएस–2025–26" "रिफरबिशमेंट ऑफ एसकेएफ मेक युआइसी–130 सीटीआर बियरिंग इन एलएचबी कोचेज फॉर 2 ईयर थ्रू ओईम (ऐज पर स्कोप ऑफ वर्क)"। **अनुमानित लागत (रू० में) :** 143719434.96, **धरोहर राशि (रू० में) :** 868600.00, **निविदा प्रपत्र का मूल्य :** रू० शून्य, **निविदा समापन की तिथि एवं अवधि :** 11.00 बजे, 31.03.2026, **संविदा की अवधि :** 24 माह, उपरोक्त ई–निविदा का पूर्ण विवरण एवं निविदा में भाग लेने हेतु भारतीय रेल की वेबसाईट संख्या http://www.ireps.gov.in पर देखे।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी./रिपेयर, यांत्रिक कारखाना, मुजाधि/यौंत्रिक – 153 पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

परियोजना हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रण
ई-निविदा सूचना संख्या: CAO-CONS-RSP-WR-2025-26-01

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए सीलबंद ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

i. ई-निविदा संख्या: CAO-CONS-RSP-WR-2025-26-01

ii. कार्य का नाम: परियोजना के लिए कंसल्टेंट (PC) की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रण (RFP) – पश्चिम रेलवे पर 397 लेवल क्रॉसिंग गेटों को समाप्त करने के लिए ROB और/या RUB/LHS/अन्य संरचनाओं/आवश्यकतानुसार रोड डायवर्जन के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन एवं DPR तैयार करने के चरण से लेकर डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि तक व्यापक परामर्श सेवाएं प्रदान करना, जिसमें अंतिम योजना के आवश्यक घटकों का विस्तृत डिजाइन, स्वीकृत योजना के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया, टेक्नो-मैनेजरियल कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट सुपरविजन सेवाएं/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, भूमि अधिग्रहण में सहायता आदि शामिल हैं।

iii. कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 325,45,93,426.17/- (रुपये तीन सौ पच्चीस करोड़ पैंतालीस लाख तिरानवे हजार चार सौ छब्बीस और सत्रह पैसे)

iv. जमा की जाने वाली धरोहर राशि : ₹ 1,64,23,100/- (रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख तेईस हजार एक सौ मात्र)

v. ऑनलाइन निविदा बिडिंग की उपलब्धता: 10.04.2026 को 11:00 बजे से 24.04.2026 को 15:00 बजे तक

vi. विस्तृत जानकारी हेतु: निविदा दस्तावेज की लागत (नॉन-रिफंडेबल), EMD, पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्य, विस्तृत निविदा शर्तों आदि की जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** वेबसाइट देखें। मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ADI 305

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

ठोस कचरा प्रबंधन विभाग (प्लानिंग)
क्रमांकः उप मुख्य अभियंता / 7510 / एसडब्ल्यूएम / प्लानिंग दिनांक 11.03.2026

ई-निविदा सूचना

विषय		:	'पूर्वी उपनगर क्षेत्र में घरेलू स्वच्छता कचरा तथा विशेष देखभाल कचरे के संग्रह हेतु पीले थैलों की आपूर्ति'
विभाग		:	ठोस कचरा प्रबंधन / उप मुख्य अभियंता (एसडब्ल्यूएम) योजना
निविदा पहचान संख्या		:	2026_MCGM_1285864_1
बोली प्रारंभ दिनांक एवं समय		:	12.03.2026 प्रातः 11:00 बजे से
बोली समाप्ति दिनांक एवं समय		:	16.03.2026 सायं 16:00 बजे तक
वेबसाइट		:	https://mahatenders.gov.in
संपर्क व्यक्ति			
a)	नाम	:	श्री हेमंत भुसारे, सहायक अभियंता (एसडब्ल्यूएम) योजना
b)	टेलीफोन	:	022-23844450
c)	मोबाइल नंबर	:	9762006449
d)	ई-मेल आईडी	:	ee1swm.pl@mcgm.gov.in

पीआरओ/3260/विज्ञा./2025-26 कार्यकारी अभियंता (एसडब्ल्यूएम) योजना

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

'मिडिल ईस्ट संकट पर राजनीति कर रही कांग्रेस', केरल में बोले पीएम मोदी, युद्ध ने हमें फिर समझाया आत्मनिर्भरता का महत्व

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कोच्चि में लगभग 10, 800 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो केरल में अवसंरचना, ऊर्जा और औद्योगिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देती हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने कहा कि केरल की जनता ने देखा है कि कांग्रेस के नेता ड्रोन निर्माण में भारत के युवाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों से अनभिज्ञ हैं। कांग्रेस नेता को यह जानकारी नहीं है कि भारत में कई कंपनियां ड्रोन का निर्माण कर रही हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि केरल के युवाओं ने ड्रोन विकसित करने के लिए स्टार्टअप शुरू किए हैं। जो व्यक्ति अपनी संकीर्ण सोच में जकड़ा रहता है, वह देश की प्रगति को कभी नहीं देख पाएगा।

मोदी ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर आप सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। याद रखिए, आज भाजपा-एनडीए सरकार सत्ता में है। जब भी हमारे देश का कोई नागरिक संकट में होता है, हम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे इराक से नर्सों को बचाना हो या यमन में आतंकवादियों के चंगुल से फादर टॉम को छुड़ाना हो, भारत आज भी संकट के समय में अपने नागरिकों को कभी नहीं छोड़ता। आज भी हमारा प्रयास युद्धग्रस्त देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की तसल्ली है कि खाड़ी के हमारे सभी मित्र देशों की सरकारें हमारे नागरिकों का ख्याल रख रही हैं। उन देशों में हमारे मिशन और दूतावास चौबीसों घंटे उनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट के बीच भी राजनीति में उतरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस जानबूझकर भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयान देकर स्थिति को और बिगाड़ रही है। ताकि हमारे लोग इस संकट में फंसे रहें, और फिर ये लोग मोदी को गाली देने वाली रीलें बनाने का अभियान शुरू कर सकें।

मोदी ने कहा कि खाड़ी में चल रहे युद्ध ने हमें एक बार फिर आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया है। हमने कोविड संकट, यूक्रेन संकट के दौरान आत्मनिर्भरता का महत्व देखा है और मौजूदा संकट ने इसे एक बार फिर साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा-एनडीए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दल आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाने में लगे हैं... इन्होंने देश को विदेशी देशों पर और भी ज्यादा निर्भर बना दिया है। आज ये सभी मिलकर अफवाहें फैलाने में लगे हैं। यहां तक कि युद्धकाल में भी कांग्रेस, वामपंथी दल और उनके सहयोगी संगठन अपनी सारी ऊर्जा देश में दहशत फैलाने और संघर्ष पैदा करने में लगा रहे हैं।

विपक्ष पर वार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबरीमाला मंदिर मामले में उनकी साझेदारी पर विचार करें। एलडीएफ सदस्यों पर सोना लूटने का आरोप है, जबकि यूडीएफ सदस्यों पर चोरी का सोना बेचने का आरोप है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, जो अब मुस्लिम लीग-माओवादी कांग्रेस (एमएमसी) बन चुका है। केरल में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस जमात और इसी तरह के अन्य संगठनों पर निर्भर है। एमएमसी कांग्रेस उन पार्टियों का समर्थन करती है जो अपने चरमपंथी एजेंडे से केरल की शांति भंग करना चाहती हैं। दूसरी तरफ, एलडीएफ का पीडीपी जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ लंबे समय से संबंध है, वही पीडीपी जो चरमपंथ फैलाने में सबसे आगे रही है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की फुकेत फ्लाइट में बड़ी खराबी, रनवे पर फंसा विमान, बाल-बाल बचे यात्री

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। हैदराबाद से फुकेत जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट फुकेत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फ्लाइट के नोज व्हील में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रनवे पर ही फंसी रह गई।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता के अनुसार, 'हम पुष्टि करते हैं कि 11 मार्च को हैदराबाद-फुकेत फ्लाइट के फुकेत हवाई अड्डे पर नोज व्हील में खराबी आ गई थी। क्रू ने सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन किया और यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। हम अपने यात्रियों, फुकेत हवाई अड्डे के अधिकारियों और सभी संबंधित पक्षों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस बीच, एयर इंडिया ने मंगलवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों मार्गों पर ईंधन सरचार्ज को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की घोषणा की और कहा कि खाड़ी क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति के कारण जेट ईंधन की कीमतों में आई भारी वृद्धि के चलते यह कदम आवश्यक हो गया है।

एक बयान में एयरलाइन ने कहा कि विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), जो किसी एयरलाइन की परिचालन लागत का लगभग

40 प्रतिशत होता है, आपूर्ति में व्यवधान के कारण मार्च 2026 की शुरुआत से इसकी कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है, 'भारत में, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख महानगरों में एटीएफ पर उच्च उत्पाद शुल्क और वैट के कारण यह दबाव और बढ़ जाता है, जिससे लागत बढ़ जाती है और एयरलाइनों के परिचालन अर्थशास्त्र पर काफी दबाव पड़ता है। बयान के अनुसार, नया ईंधन अधिभार तीन चरणों में लागू किया जाएगा और एयर इंडिया एक्सप्रेस सहित सभी उड़ानों पर लागू होगा।

पहला चरण 12 मार्च से की गई सभी नई बुकिंग पर लागू होगा। इस चरण के तहत, भारत के भीतर घरेलू मार्गों और सार्क देशों के लिए उड़ानों पर 399 रुपये का ईंधन अधिभार लगेगा, जो पहले लागू नहीं था। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व के लिए उड़ानों पर 10 अमेरिकी डॉलर का अधिभार लगेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के मार्गों के लिए, अधिभार 40 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जबकि अफ्रीका के लिए उड़ानों पर अधिभार 60 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि सिंगापुर आने-जाने वाली उड़ानों पर फिलहाल ईंधन अधिभार नहीं लगता है, लेकिन यह पहले चरण से लागू होगा।

अतिरिक्त शुल्क विस्तार का दूसरा चरण 18 मार्च से की गई बुकिंग पर लागू होगा। यूरोप जाने वाली उड़ानों पर ईंधन अधिभार 100 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 125 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले मार्गों पर अधिभार 150 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 200 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया सहित सुदूर पूर्व के बाजारों को कवर करने वाले तीसरे चरण की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

एयर इंडिया ने कहा कि लागू होने की तारीख से पहले जारी किए गए टिकटों पर नया अधिभार नहीं लगेगा, जब तक कि यात्री तारीख या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव का अनुरोध न करें जिसके लिए किराए की पुनर्गणना की आवश्यकता हो।

जगन मोहन रेड्डी का टीडीपी सरकार पर बड़ा हमला बोले- नायडू ने सरकारी खजाना खाली कर दिया

अमरावती। वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को कहा कि चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा पेश किया गया बजट भ्रामक आंकड़ों और झूठे दावों से भरा है। जगन ने कहा कि चंद्रबाबू के सत्ता में आने के बाद से राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। हमारे पांच साल के शासनकाल में कुल कर्ज लगभग 33 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन चंद्रबाबू के शासन के सिर्फ दो वर्षों में ही कर्ज 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

जगन ने कहा कि जब भी चंद्रबाबू सत्ता में आते हैं, राजस्व घट जाता है और कर्ज बढ़ जाता है। इसका कारण स्पष्ट है - व्यापक भ्रष्टाचार और संसाधनों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग। सरकारी जमीनें निजी रियल एस्टेट कंपनियों को कौड़ियों के भाव में सौंपी जा रही हैं। विशाखापत्तनम में हजारों करोड़ रुपये की जमीनें रिश्तेदारों और सहयोगियों को आवंटित की जा रही हैं। जगन रेड्डी ने टीडीपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार खजाने में न्यूनतम शेष राशि भी नहीं रख पा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा सत्र जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय नाटक, नुक्कड़ नाटक और आत्म-प्रशंसा में सिमट गए। हमने सुपर सिक्स योजनाओं के वादों के बारे में सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महिलाओं से किए गए वादों का क्या हुआ? गरीबों के लिए आवास का क्या हुआ? पिछले दो वर्षों में क्या उन्होंने गरीबों को एक भी जमीन दी है या एक भी घर बनाया है?उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। हालांकि, जब चंद्रबाबू राजनीतिक सभाएं आयोजित करते हैं, तो वे आंगनवाड़ी

इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का भावुक संदेश, बोले- बंगाल मुझे जाने नहीं देगा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद सी. वी. आनंद बोस ने राज्य के लोगों के नाम एक भावुक खुला पत्र लिखा है। करीब तीन साल चार महीने तक पद पर रहने के बाद उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दिया और विदाई से पहले बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।

नवंबर 2022 में जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें बंगाल से विशेष लगाव है। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके उपनाम 'बोस' के पीछे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का प्रेरक प्रभाव रहा है।

अपने पत्र की शुरुआत में आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के लोगों को 'प्रिय भाई-बहन' कहकर संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता से मिले स्नेह, सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद जताया।

उन्होंने लिखा कि भले ही राज्यपाल के रूप में उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई हो, लेकिन बंगाल के साथ उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा। उनके शब्दों में, यह राज्य अब उनके लिए 'दूसरा घर' बन चुका है और वह भविष्य में भी इससे जुड़े रहेंगे।

अपने संदेश में उन्होंने बंगाल की जनता के साथ बिताए अनुभवों को याद किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों से मुलाकात, बच्चों का उत्साह, युवाओं का आत्मविश्वास और बुजुर्गों का स्नेह उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि इन पलों ने उन्हें इस राज्य और यहां के लोगों से गहराई से जोड़ दिया।

एलपीजी की किल्लत पर भड़के संजय राउत, पीएम मोदी को याद दिलाया 'नाले से गैस' वाला बयान

मुम्बई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार के आश्वासन झूठे साबित हुए हैं। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने एलपीजी और ईंधन की कमी के कारण रेस्तरां और अन्य उद्योगों के कथित तौर पर बंद होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति है। व्यावसायिक और घरेलू गैस की कमी है। जब संघर्ष शुरू हुआ, तब मोदी सरकार ने कहा था कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के आश्वासन विफल रहे हैं। मुंबई और अन्य शहरों में रेस्तरां बंद हो रहे हैं।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने कहा कि वाहन क्षेत्र में भी खतरा मंडरा रहा है। मोरबी में टाइल उत्पादन बंद हो रहा है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह रहे हैं। पीएम मोदी एक वैज्ञानिक हैं, और कुछ साल पहले उन्होंने नाले से गैस बनाने का प्रयोग किया था। उन्हें मुंबई में भी ऐसा ही एक संयंत्र शुरू करना चाहिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के बीच एलपीजी की कमी हो गई है। इसके जवाब में, केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत घरों, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए अधिक आवंटन किया गया है, जबकि कई क्षेत्रों में वाणिज्यिक वितरण प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ईरान हमलों के बीच कतर का ऐलान-अब मध्यस्थता संभव नहीं, हम खुद झेल रहे अटैक

बेरूत। पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच कतर ने साफ कहा है कि वह ईरान के लिए किसी भी तरह की मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभा सकता। कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज अल-खुलैफी ने कतर के मीडिया नेटवर्क अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में यह बयान दिया। अल-खुलैफी ने कहा कि कतर और ओमान दोनों ने लंबे समय तक ईरान और पश्चिमी देशों के बीच बातचीत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब इन देशों पर भी हमले हो रहे हैं, तब मध्य की भूमिका निभाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम हमलों के बीच मध्यस्थता नहीं कर सकते। ईरान को यह समझाना चाहिए कि क्षेत्रीय देश उसके दुश्मन नहीं हैं।' इस बीच दोहा में बुधवार सुबह संभावित ईरानी हमले की चेतावनी जारी की गई। समाचार एजेंसी एपी के एक पत्रकार के अनुसार राजधानी के ऊपर हवाई रक्षा मंत्रियों ने आने वाले हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई की, जिसके दौरान धमाकों की आवाजें भी सुनी गईं। विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण अब कई खाड़ी देश भी सीधे खतरे की स्थिति में आ गए हैं। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो क्षेत्र में कूटनीतिक प्रयास और शांति वार्ताएं और कठिन हो सकती हैं।

जापानी मंत्री पर चीनी मीडिया की नस्लवादी टिप्पणी पर बवाल

टोक्यो ने बीजिंग को भेजा कड़ा संदेश

टोक्यो। उइगर अधिकार संगठन विश्व उइगर कांग्रेस (डब्ल्यूयूसी) ने जापान की विदेश मामलों की संसदीय उपमंत्री अर्फ़िया एरी के खिलाफ चीनी मीडिया में प्रकाशित कथित नस्लवादी टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। संगठन का कहना है कि यह घटना उइगर समुदाय के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डराने-धमकाने की कोशिश का उदाहरण है। डब्ल्यूयूसी के अनुसार विवाद 27 फरवरी को तब शुरू हुआ जब चीनी वेबसाइट सिना.कॉम पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में अरफिया एरी के जातीय मूल को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

रिपोर्ट में उन्हें 'फ्रंटियर पॉइजन' और 'टॉक्सिक' जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। बाद में ये टिप्पणियां ग्लोबल टाइम्स से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए टिकटॉक पर भी साझा की गईं, जिससे ऑनलाइन विवाद और बढ़ गया। अरफिया एरी के माता-पिता पूर्वी तुर्किस्तान (शिनजियांग क्षेत्र) से आते हैं। उनका परिवार 1999 में जापानी नागरिक बना था। राजनीति में आने से पहले एरी एक अकादमिक थीं और संयुक्त राष्ट्र में अधिकारी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। 2023 में वह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जापान की संसद के लिए चुनी गईं और उइगर मूल की पहली नेता बनीं जिन्हें किसी राष्ट्रीय संसद में चुना गया।

इस विवाद के बाद जापान सरकार ने चीन के सामने औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। जापान ने इसे एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि का अभूतपूर्व अपमान बताया। डब्ल्यूयूसी के अध्यक्ष तुर्गुंजन अलावदुन ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि उइगर समुदाय को किस तरह की अमानवीय भाषा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।उन्होंने कहा कि यह बयानबाजी चीन की कथित ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी विदेशों में भी उइगर समुदाय को निशाना बनाने की नीति से जुड़ी हुई है। डब्ल्यूयूसी ने जापान के कूटनीतिक कदम का समर्थन करते हुए दुनिया के अन्य देशों से भी अपील की है कि वे नस्लवादी भाषा और भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं।

ईरान ने होर्मुज में भारत जा रहे थाई कार्गो शिप पर किया हमला, जंग के बीच वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

तेहरान। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री उत्थान में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बड़ा हमला सामने आया है। भारत की ओर जा रहे एक थाई मालवाहक जहाज पर प्रक्षेप्य से हमला किया गया, जिससे वैश्विक समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रिपोर्टों के अनुसार थाईलैंड के झंडे वाला बल्क कैरियर मयूरी नारी मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहा था, तभी उस पर प्रक्षेप्य से हमला किया गया। यह जहाज भारत की ओर जा रहा था और घटना ओमान के तट से करीब 11 समुद्री मील (लगभग 18 किलोमीटर) उत्तर में हुई। रॉयल थाई नेवी के अनुसार जहाज पर सवार 20 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी तीन लोग जहाज पर बंधक होने की धमकी है और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उसी दिन कम से कम दो जहाजों पर हमले की खबर सामने आई है। इससे इस महत्वपूर्ण वैश्विक समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री उत्थान में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल और माल तैनात होती है। ईरान ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेनाएं बढ़ा दी हैं और तेल टैंकरों की हालत को रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंका भी बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (ळण्र्ऊँ) ने चेतावनी दी है कि अगर इस समुद्री मार्ग में लंबे समय तक बाधा आती है, तो इससे वैश्विक व्यापार, तेल आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है।

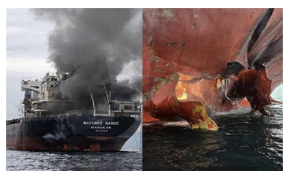

ईरान युद्ध के बीच मालदीव की चेतावनी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत का साथ जरूरी

माले। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। मारिया दीदी, जो मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री हैं, ने कहा है कि मालदीव की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर होने के कारण बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वर्तमान संकट के दौर में दक्षिण एशियाई देशों को मिलकर काम करना चाहिए और भारत जैसे साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी जा सके।

मारिया दीदी ने कहा कि मालदीव महत्वपूर्ण सी-लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों के बीच स्थित है। इसलिए यह जरूरी है कि दक्षिण एशियाई देश अलग-अलग न सोचें बल्कि एकजुट होकर क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करें। उनका कहना था कि केवल नारेबाजी वाली विदेश नीति से काम नहीं चलेगा, बल्कि भारत और अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को किए गए संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ युद्ध अब 12वें दिन में पहुंच चुका है।इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य ठिकानों और कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से दोनों पक्ष लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और संघर्ष अब लेबनान, इराक और कई खाड़ी देशों तक फैल चुका है। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है

श्रीलंका अदालत का बड़ा फैसला अमेरिका हमले में मारे गए 84 नाविकों के शव ईरान को सौंपने का आदेश

कोलंबो। मिडिल ईस्ट युद्ध के असर अब हिंद महासागर तक दिखाई देने लगे हैं। इसी बीच श्रीलंका की एक अदालत ने अमेरिकी हमले में मारे गए 84 ईरानी नाविकों के शव ईरान के दूतावास को सौंपने का आदेश दिया है। गॉल के मुख्य मजिस्ट्रेट समीरा डोडांगोडा ने गाले नेशनल हॉस्पिटल के निदेशक को निर्देश दिया कि अस्पताल में रखे शवों को ईरान के दूतावास को सौंप दिया जाए। यह आदेश गाले हार्बर पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया। पिछले सप्ताह श्रीलंका सरकार ने बताया था कि आईरिस डेना फ्रिगेट नामक ईरानी युद्धपोत पर संयुक्त राज्य अमेरिका की

पनडुब्बी द्वारा हमला किया गया था, जिससे जहाज गाले के तट के पास डूब गया। इस घटना में जहाज पर सवार 84 नाविकों की मौत हो गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक यह युद्धपोत विशाखापत्तनम, भारत से लौट रहा था, जहां उसने एक नौसैनिक बेड़े की समीक्षा कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

इजरायली हमलों से लेबनान तबाह

रोते-बिलखते 7.8 लाख लोगों ने छोड़े घर, मानवीय स्थिति हुई भयावह

बेरूत। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के 12वें दिन हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर अब लेबनान में दिखाई दे रहा है, जहां लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली हमलों के कारण लेबनान में करीब 7, 80, 000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। लगातार हो रही बमबारी और सैन्य कार्रवाई के कारण कई शहरों और गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं।

कतर की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी लेबनान के सफ अल हवा इलाके में एक इजरायली ड्रोन हमले में एक एसयूवी को घुमाया गया। हमले के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल बन गया। इस बीच मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने गंभीर आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने लेबनान के योहमोर शहर के रिहायशी इलाकों में सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। सफेद फॉस्फोरस एक रासायनिक पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। इसे आमतौर पर सेना के ठिकानों की आड़ बनाने या हवाई हमलों के लिए लक्ष्य चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल करती है। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में कई इजरायली सैन्य ठिकानों को रॉकेट से घुमाया है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)